बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 41 ● नई दिल्ली ● वीरवार 20 नवम्बर 2025 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन

बी-2/370, सुल्तानपुरी

दिल्ली-86

डायट में कला-संस्कृति महोत्सव में नवाचार की गूंज, प्रतिभागी शिक्षक हुए सम्मानित

फतेहपुर। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) में बुधवार को कला, क्राफ्ट एवं संस्कृति महोत्सव का भव्य आयोजन हुआ। प्राचार्या/उप शिक्षा निदेशक आरती गुप्ता व नोडल प्रभारी मानवेन्द्र सिंह ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। महोत्सव का उद्देश्य शिक्षकों व प्रशिक्षुओं में रचनात्मकता, अभिव्यक्ति कौशल और भारतीय सांस्कृतिक विरासत के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना रहा। चित्रकला, क्राफ्ट प्रदर्शनी, वाल पेंटिंग, पपेट शो, अभिनव रंगमंच और लोक-सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने कार्यक्रम में चार चाँद लगा दिए। चित्रकला व मूर्ति कला में संध्या गौतम (प्रथम), अवंतिका खाजपेई (द्वितीय), सृष्टि उमराव (तृतीय) रहीं।

एसआईआर के बाद बंगाल में 28 मौतें, ईसी जिम्मेदार- ममता

कोलकाता।

ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को ठहराया जिम्मेदार कार्यकर्ताओं पर अत्यधिक दबाव का आरोप

बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) की प्रक्रिया शुरू होने के बाद से राज्य के विभिन्न हिस्सों से मौत की खबरें सामने आ रही हैं। बुधवार सुबह मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने एक्स हैंडल पर चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला। उन्होंने लिखा कि एसआइआर शुरू होने के बाद से अब तक 28 लोगों की मौत हो चुकी है और इसके लिए आयोग का अनियोजित निर्णय जिम्मेदार है। चुनाव आयोग ने अक्टूबर के अंत में बंगाल में एसआइआर की शुरुआत की थी। आयोग ने स्पष्ट किया था कि जिनके नाम 2002 की मतदाता सूची में दर्ज हैं या जिनके परिवारों में नाम मौजूद हैं, उन्हें किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बावजूद, लोगों के बीच असुरक्षा और भय का माहौल बना हुआ है। हजारों सवाल और आशंकाएं लोगों के मन में घर कर चुकी हैं।

निर्वासित होने के डर से आत्महत्या- ममता

एसआइआर लागू होने के बाद कई लोगों ने कथित तौर पर निर्वासित होने के डर से आत्महत्या कर ली है। यह स्थिति बेहद दुखद है और समाज में

अस्थिरता पैदा कर रही है। स्थानीय स्तर पर यह भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) पर अत्यधिक काम का दबाव डाला जा रहा है, जिसके कारण वे मानसिक तनाव में आकर आत्महत्या कर रहे हैं।

फंदे से लटका मिला महिला बीएलओ का शव

बुधवार सुबह मालबाजार में एक महिला बीएलओ का शव फंदे से लटका हुआ मिला। परिवार का दावा है कि वह आत्महत्या एसआइआर से जुड़े काम के दबाव के कारण हुई है। इस घटना ने पूरे राज्य में बहस को और तेज कर दिया है। विपक्ष और सामाजिक संगठनों ने भी इस मामले को गंभीरता से उठाया है।

कार्यकर्ताओं पर असहनीय दबाव पड़ रहा है- ममता

इस संदर्भ में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने एक्स हैंडल पर गुस्सा जाहिर किया। उन्होंने लिखा कि मैंने आज एक और बीएलओ को खो दिया। वह महिला आंगनबाड़ी में काम करती थी और एसआइआर का इतना दबाव नहीं झेल सकी। ममता ने आरोप लगाया कि आयोग ने बिना योजना के काम शुरू किया है, जिसके कारण कार्यकर्ताओं पर असहनीय दबाव पड़ रहा है और अनमोल जानें जा रही हैं।

एसआइआर अतिवादी निर्णय है- ममता

ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि जिस काम को पूरा करने में पहले तीन साल लगते थे, उसे अब राजनीतिक कारणों से मात्र दो महीने में पूरा करने का दबाव डाला जा रहा है। उन्होंने इसे अतिवादी निर्णय करार दिया और कहा कि इस जल्दबाजी के कारण आम नागरिकों और कर्मचारियों की जान पर बन आई है।

आयोग अपने फैसले पर पुनर्विचार करे- ममता

मुख्यमंत्री ने चुनाव आयोग से स्थिति को संभालने के लिए तत्काल कदम उठाने की अपील की। उन्होंने कहा कि आयोग को चाहिए कि वह अपने फैसले पर पुनर्विचार करे और कार्यकर्ताओं पर पड़ रहे दबाव को कम करे। ममता ने चेतावनी दी कि यदि आयोग ने समय रहते कार्रवाई नहीं की, तो राज्य में और भी गंभीर परिणाम देखने को मिल सकते हैं।

राहुल के खिलाफ 272 रिटायर्ड जजों-अफसरों का लेटर

कहा- ईसी की छवि बिगाड़ रही कांग्रेस; राहुल वोट चोरी पर 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके

नई दिल्ली लगभग 300 सेवानिवृत्त न्यायाधीशों, नौकरशाहों, पूर्व सैन्य अधिकारियों और राजनयिकों के एक समूह ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस पर विपक्षी दल के वोट चोरी अभियान के तहत चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने का आरोप लगाया है। समूह ने एक खुला पत्र जारी कर कहा है कि ये आरोप संस्थागत संकट की आड़ में राजनीतिक हताशा को छिपाने का प्रयास हैं। इस पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले 272 लोगों में 16 सेवानिवृत्त न्यायाधीश, 123 पूर्व नौकरशाह (जिनमें 14 राजदूत भी शामिल हैं) और 133 सेवानिवृत्त सशस्त्र बल अधिकारी शामिल हैं। इन 272 हस्ताक्षरकर्ताओं में जम्मू-कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद, पूर्व रॉ प्रमुख संजीव त्रिपाठी, पूर्व आईएफएस लक्ष्मी पुरी और अन्य प्रमुख लोग शामिल हैं। यह घटनाक्रम राहुल गांधी द्वारा एसआईआर प्रक्रिया और चुनाव आयोग की लगातार आलोचना और उन पर वोट चोरी को बढ़ावा देने का आरोप लगाने के बीच हुआ है। कांग्रेस ने कहा है कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान चुनाव आयोग का आचरण बेहद निराशाजनक रहा है और मांग की है कि चुनाव आयोग तुरंत यह साबित करे कि वह भाजपा के प्रभाव में काम नहीं कर रहा है। राष्ट्रीय संवैधानिक प्राधिकारियों पर हमला शीर्षक वाले पत्र में हस्ताक्षरकर्ताओं ने कहा कि हम, नागरिक समाज के वरिष्ठ नागरिक, इस बात पर अपनी गंभीर चिंता व्यक्त करते हैं कि भारत के लोकतंत्र पर बल प्रयोग से नहीं, बल्कि इसकी आधारभूत संस्थाओं के विरुद्ध जहरीली बयानबाजी की बढ़ती लहर से हमला हो रहा है। कुछ राजनीतिक नेता, वास्तविक नीतिगत विकल्प प्रस्तुत करने के बजाय, अपनी सटकीय राजनीतिक रणनीति के तहत भड़काऊ लेकिन निराधार आरोपों का सहारा लेते हैं। भारतीय सशस्त्र बलों की वीरता और उपलब्धियों पर प्रश्नचिह्न लगाकर, और न्यायपालिका की निष्पक्षता, संसद और उसके संवैधानिक पदाधिकारियों पर प्रश्नचिह्न लगाकर उन्हें कलंकित करने के उनके प्रयासों के बाद, अब भारत के चुनाव आयोग की बारी है कि वह अपनी ईमानदारी और प्रतिष्ठा पर व्यवस्थित और षड्यंत्रकारी हमलों का सामना करे। कांग्रेस नेता की आलोचना करते हुए, हस्ताक्षरकर्ताओं ने कहा कि उन्होंने बार-बार चुनाव आयोग पर हमला बोला है और कहा है कि उनके पास इस बात के स्पष्ट प्रमाण हैं कि चुनाव आयोग वोट चोरी में शामिल है।

ओवैसी खानदानी नेता, गुनाह इतना कि वह मुसलमान हैं - पूर्व गोंडा सांसद बृजभूषण सिंह का बड़ा बयान

गोंडा।

अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने एक यूट्यूबर से बातचीत के दौरान ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओवैसी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि ओवैसी सीधी बात करते हैं। वह खानदानी नेता हैं। गुनाह सिर्फ इतना है कि वह मुसलमान हैं। उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव में उनकी पार्टी ने पांच सीटें जीती है। बी टीम के सवाल पर उन्होंने कहा कि उन्होंने सीधा चुनाव लड़ा है। उन्होंने दोनों पार्टियों भाजपा गठबंधन और लालू एंड कंपनी की आलोचना की है। इस पर उन्होंने

बिहार में पांच सीटें मिली है। उन्होंने कहा इस तरह से मायावतों को भी बी टीम आप बता देंगे। पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह का साफ इशारा था कि लोकतंत्र में हर किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। कोई भी भाजपा की बी टीम नहीं है। ओवैसी खानदानी नेता है। गुनाह इतना है कि वह मुसलमान है। सिंह का यह बयान तेजी से वायरल हो रहा है। आप को बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बिहार की जिन 25 सीटों पर चुनाव लड़ा, उनमें से पांच अपने नाम कर ली हैं। इनमें जोकिहाट, बहादुरगंज, कोचाधामन, अमौर और बायसी सीटें शामिल हैं। ये सभी पांच सीटें मुस्लिम बहुल सीमांचल इलाके में आती हैं। गौरतलब है कि 2020 में भी पांच सीटों पर ओवैसी ने जीत दर्ज की थी लेकिन बाद में चार विधायक पार्टी को छोड़कर राजद का दामन थाम लिया था। हालांकि इस बार देखना होगा कि क्या ये विधायक पार्टी के साथ रहते हैं या फिर पार्टी बदल लेते हैं?

ये बच्चों को गैस चैंबर में डालने जैसा होगा, दिल्ली में प्रदूषण के बीच स्कूलों में आउटडोर खेलों पर सुप्रीम कोर्ट नाराज

नई दिल्ली। दिल्ली में बिगड़ती वायु गुणवत्ता के बीच, सुप्रीम कोर्ट ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग से आग्रह किया कि वह दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र के स्कूलों को नवंबर और दिसंबर में होने वाले खेल और एथलेटिक कार्यक्रमों को स्थगित करने का निर्देश देने पर विचार करे। कोर्ट ने सुझाव दिया कि इन गतिविधियों को उन महीनों में स्थानांतरित किया जाए जब प्रदूषण का स्तर सुधर जाए। भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंदन की पीठ ने यह टिप्पणी तब की जब वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) खतरनाक स्तर पर बने रहने के दौरान खेल आयोजनों को लेकर चिंता जताई गई थी।

न्यायमित्र के रूप में उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता अपराजिता सिंह ने पीठ

को सूचित किया कि एनसीआर के कई स्कूल प्रदूषण में भारी वृद्धि के बावजूद नवंबर में अपनी वार्षिक खेल प्रतियोगिताएँ आयोजित करने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी, बच्चे सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं। अभी खेल आयोजन आयोजित करना उन्हें गैस चैंबर में डालने जैसा है। इस दलील पर ध्यान देते हुए, पीठ ने सीएक्यूएम से ऐसे आयोजनों को पुनर्निर्धारित करने के लिए उचित निर्देश जारी करने पर विचार करने को कहा। न्यायालय को यह भी बताया गया कि स्कूली खेल गतिविधियों को स्थगित करने की मांग वाली एक समान याचिका आज ही बाद में दिल्ली उच्च न्यायालय में सूचीबद्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि उच्च न्यायालय इस मामले में उचित आदेश जारी कर सकता है। यह टिप्पणी एमसी मेहता मामले की सुनवाई के दौरान आई, जिसमें न्यायालय एनसीआर में वायु प्रदूषण की स्थिति की निगरानी कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया है कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में ग्रैप-3 के लागू होने के बाद से, जिसके कारण निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, बेरोजगार निर्माण श्रमिकों को निर्वाह भत्ता दिया जाए।

नीतीश का इस्तीफा, आज 10वीं बार लेंगे शपथ

- नीतीश कुमार 10वीं बार बनेंगे बिहार के मुख्यमंत्री
- एनडीए विधायक दल की बैठक में लगी मुहर
- गांधी मैदान में समारोह, 2 मंच, 150 मेहमान,
- पीएम मोदी समेत 11 सूबों के सीएम शामिल होंगे

नई दिल्ली।

बिहार विधानसभा चुनाव में बंपर जीत के बाद आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक बार फिर से विधायक दल की बैठक में नेता चुन लिया गया। इसका मतलब साफ है कि वह 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। गांधी मैदान में 20 तारीख को वह मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ उपमुख्यमंत्री के तौर पर सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी एक बार शपथ लेते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा गठबंधन में शामिल अन्य दलों की ओर से मंत्रियों का भी शपथ ग्रहण होगा। शपथ ग्रहण भव्य तरीके से किया जाएगा। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कई केंद्रीय मंत्री के अलावा भाजपा और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। इससे

पहले बुधवार को पटना स्थित अपने आवास पर हुई जनता दल (यूनाइटेड) विधायक दल की बैठक में नीतीश कुमार को सर्वसम्मति से अपना नेता चुन लिया गया। बैठक के बाद जदयू सांसद संजय झा और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने नीतीश कुमार को बधाई दी। भारतीय जनता पार्टी के नेता सम्राट चौधरी को बिहार में भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया, जबकि विजय सिन्हा उपनेता चुने गए। एनडीए ने 2025 के बिहार चुनावों में ऐतिहासिक प्रचंड जीत दर्ज की, जिसमें 243 में से 202 सीटें जीतीं, जबकि महागठबंधन केवल 35 सीटें ही हासिल कर सका। इस गठबंधन ने 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा में तीन-चौथाई बहुमत हासिल किया, जो दूसरी बार है जब एनडीए ने राज्य चुनावों में 200 सीटों का आंकड़ा पार किया। 2010 में, इसने 206 सीटें जीती थीं। एनडीए में, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने 89 सीटें, जनता दल (यूनाइटेड) ने 85, लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) (एलजेपीआरवी) ने 19, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (सेक्युलर) (एचएएमएस) ने पांच और राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने चार सीटें जीतीं। विपक्षी दलों में, राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने 25 सीटें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने छह, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) (लिबरेशन) [सीपीआई (एमएल) (एल)] ने दो, भारतीय समावेशी पार्टी (आईआईपी) ने एक और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) [सीपीआई (एम)] ने एक सीट जीती।

हम सब दोषी नहीं- कश्मीरियों पर हो रहे संदेह पर उमर अब्दुल्ला का दर्द

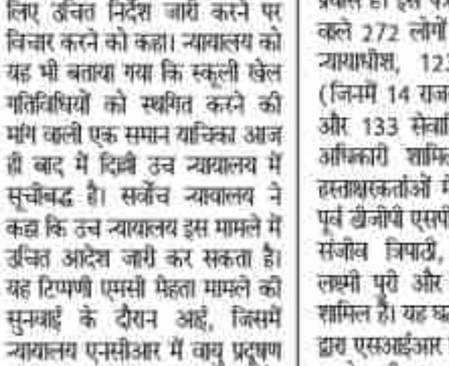

श्रीनगर। जम्मू एवं कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि 10 नवंबर को दिल्ली में हुए कार विस्फोट के बाद की जांच में किसी भी निर्दोष कश्मीरी मुसलमान पर संदेह नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए जिम्मेदार लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि दिल्ली में जो कुछ हुआ (दिल्ली आतंकी विस्फोट) उसके लिए मुट्ठी भर लोग जिम्मेदार हैं। लेकिन ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की गई जैसे हम सब दोषी हैं, जैसे हम सब इसमें शामिल हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि आज, दिल्ली में जम्मू-कश्मीर के पंजीकरण वाली गाड़ी चलाना अपराध माना जाता है। जब मेरे साथ ज्यादा सुरक्षा नहीं होती, तो मैं भी सोचता हूं कि गाड़ी निकालूं या नहीं, कोई मुझे किनारे रोककर मेरी पहचान और वहां आने का उद्देश्य पूछ लेता है। यह बयान घाटी के कई निवासियों द्वारा यह चिंता जताए जाने के बाद आया है कि दिल्ली में हुए कार विस्फोट के बाद, जिसमें कम से कम 12 लोग मारे गए थे, देश के बाकी हिस्सों में ज्यादातर कश्मीरी छात्रों या पेशेवरों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। इससे पहले, जम्मू-कश्मीर पुलिस ने अन्य राज्यों की सुरक्षा एजेंसियों के साथ संयुक्त अभियान में सफेदपोश आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया था और अल फलाह में कार्यरत दो कश्मीरी डॉक्टरों डॉ. मुजम्मिल गनई और डॉ. अदील राथर सहित सात लोगों को गिरफ्तार किया था। साथ ही, फरीदाबाद से लगभग 3,000 किलोग्राम विस्फोटक और उपकरण बरामद किए थे।

मोदी ने 9 करोड़ किसानों के खाते में भेजे 18,000 करोड़, जारी की पीएम-किसान की 21वीं किस्त

नई दिल्ली।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को तमिलनाडु के कोयंबटूर में एक समारोह में लाभार्थियों को पीएम-किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त जारी की।

नौ करोड़ लाभार्थियों के बैंक खातों में 18,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे हस्तांतरित की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने प्राकृतिक खेती प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और दक्षिण भारत राष्ट्रीय कृषि शिखर सम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने स्थानीय किसानों से मुलाकात की और उनसे बातचीत की, तथा प्रदर्शनी का निरीक्षण किया, जिसमें विभिन्न कृषि उत्पादों के साथ-साथ पौधों और फसलों की वृद्धि दिखाने के लिए एक कोना भी प्रदर्शित किया गया था। प्रधानमंत्री के साथ तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि भी थे। दक्षिण भारत प्राकृतिक खेती शिखर सम्मेलन 2025, जो 19-21 नवंबर तक आयोजित किया जा रहा है, का आयोजन तमिलनाडु प्राकृतिक खेती हितधारक मंच द्वारा किया जा रहा है। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य टिकाऊ, पर्यावरण-अनुकूल और रसायन-मुक्त कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना और भारत के कृषि भविष्य के लिए एक व्यवहार्य, जलवायु-अनुकूल और आर्थिक रूप से टिकाऊ मॉडल के रूप में प्राकृतिक और पुनर्योजी खेती की ओर बदलाव को गति देना है। शिखर सम्मेलन में किसान-उत्पादक संगठनों और ग्रामीण उद्यमियों के लिए बाजार संपर्क बनाने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा, साथ ही जैविक आदानों, कृषि-प्रसंस्करण, पर्यावरण-अनुकूल पैकेजिंग और स्वदेशी तकनीकों में नवाचारों का प्रदर्शन भी किया जाएगा। इस कार्यक्रम में तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के 50,000 से अधिक किसान, प्राकृतिक कृषि व्यवसायी, वैज्ञानिक, जैविक आदान आपूर्तिकर्ता, विक्रेता और हितधारक भाग लेंगे। इससे पहले, प्रधानमंत्री मोदी ने आंध्र प्रदेश का दौरा किया, जहाँ उन्होंने श्री सत्य साईं बाबा के जन्म शताब्दी समारोह में भाग लिया। सभा को संबोधित करते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सेवा के बिना भक्ति, करुणा के बिना ज्ञान और सामाजिक योगदान के बिना कर्म का कोई अर्थ नहीं है।

सीएम योगी ने की विकास कार्ययोजना की समीक्षा, कहा- 'जनहित से जुड़े कार्यों के लिए धनराशि की कमी नहीं होगी'

लखनऊ।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को मेरठ, कानपुर और मथुरा-वृंदावन के समग्र नगरीय विकास की कार्ययोजना की समीक्षा करते हुए कहा कि इन नगरों का विकास केवल सड़कों और इमारतों के निर्माण तक सीमित न हो, बल्कि उनका स्वरूप ऐसा बने जिसमें स्थानीय पहचान, इतिहास, संस्कृति और आधुनिक सुविधाओं का संतुलन दिखे।

उन्होंने निर्देश दिया कि योजनाएं चरणबद्ध ढंग से लागू हों, कार्य समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरे किए जाएं और नागरिकों को इसका प्रत्यक्ष लाभ दिखे। मुख्यमंत्री ने मेरठ में प्रस्तावित बिजली बम्बा बाईपास को लखनऊ ग्रीन कॉरिडोर की तर्ज पर पीपीपी मोड में विकसित करने की संभावना तलाशने के निर्देश दिए। बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तीनों मंडलों के मंडलायुक्तों ने

बारी-बारी से अपनी कार्ययोजना से अवगत कराया।

बताया गया कि अयोध्या, वाराणसी, गोरखपुर और प्रयागराज की तर्ज पर अब मेरठ, कानपुर और मथुरा-वृंदावन के लिए भी समेकित विकास मॉडल अपनाया जा रहा है।

जनप्रतिनिधियों से विमर्श और विभागों के बीच समन्वय हो

जनप्रतिनिधियों से विमर्श और विभागों के बीच समन्वय के आधार पर इन शहरों में कुल 478 परियोजनाओं की रूपरेखा तैयार की गई है। इनमें मेरठ में 111, कानपुर में 109 और मथुरा-वृंदावन में 258 परियोजनाओं का विकास प्रस्तावित है। इन परियोजनाओं को अल्पकालिक, मध्यमकालिक और दीर्घकालिक श्रेणी में विभाजित कर स्पष्ट समयसीमा तय की गई है।

शहरी ढांचा तैयार हो जो यातायात को सुगम बनाए

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं के लिए नवाचार, बेहतर प्रबंधन और वित्तीय संयोजन

उन्होंने निर्देश दिया कि योजनाएं चरणबद्ध ढंग से लागू हों, कार्य समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरे किए जाएं और नागरिकों को इसका प्रत्यक्ष लाभ दिखे।

पर ध्यान दिया जाए। उन्होंने अधिकारियों को रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पर निजी क्षेत्र का सहयोग लेने और जहां संभव हो वहां पीपीपी मोड अपनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विकास का उद्देश्य ऐसा शहरी ढांचा तैयार करना है जो यातायात को सुगम बनाए, पैदल यात्रियों और सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता दे, हरे-भरे शहरों की दिशा में आगे बढ़े और स्थानीय पहचान को मजबूत करे। उन्होंने कहा कि परियोजनाओं के लिए यदि अतिरिक्त बजट की आवश्यकता होगी तो उसे उपलब्ध कराया जाएगा।

पीएम मोदी ने श्री सत्य साईं बाबा के सम्मान में स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किए

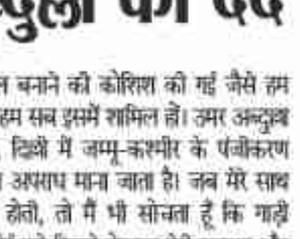

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को दिवंगत आध्यात्मिक गुरु श्री सत्य साईं बाबा के जीवन, शिक्षाओं और विरासत के सम्मान में 100 रुपये का स्मारक सिक्का और डाक टिकटों का एक सेट जारी किया। मोदी ने श्री सत्यसाईं जिले में साईं बाबा के जन्म शताब्दी समारोह में भाग लिया। समारोह के दौरान मोदी ने वहां साईं बाबा की महासमाधि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू, उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण, पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी और के राम मोहन नायडू तथा अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन सहित अन्य लोग उपस्थित थे।

शेख हसीना को फांसी की सज़ा -राजनीतिक तनाव और संभावनाओं का विश्लेषण

वैश्विक स्तर पूरी दुनियाँ का ध्यान खींचने वाला विषय बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को बांग्लादेश की इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल (आईसीटी -बीडी) द्वारा मानवता के खिलाफ अपराध के आरोपों में मृत्यु दण्ड सुनाए जाने के बाद,भारत- बांग्लादेश प्रत्यर्पण संधि (जो 28 जनवरी 2013 में लागू है) पर सवाल उठे हैं कि क्या भारत उन्हें वापस भेजेगा। यह मामला सिर्फ कानूनी नहीं है,इसमें कूटनीति, मानवाधिकार, घरेलू राजनीति और क्षेत्रीय स्थिरता जैसे कई आयाम जुड़े हैं। इस आलेख में,हम पहले प्रत्यर्पण संधि (विशेष रूप से अनुच्छेद 8) की कानूनी व्याख्या करेंगे, उसके बाद हसीना के मामले में भारत की स्थिति, प्रत्यर्पण करने या न करने के संभावित रास्ते, और अंत में दीर्घकालीन रणनीतिक परिणामों का विश्लेषण करेंगे। मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूं कि भारत संधि के लूपहोल्स (जैसे राजनीतिक प्रकृति) का इस्तेमाल कर अस्वीकार कर सकता है, इससे बांग्लादेश में भारत-विरोधी भावनाएं भड़क सकती हैं?,लेकिन सरकार द्विपक्षीय संबंधों (व्यापार, रोहिंग्या मुद्दा) को प्राथमिकता देगी। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत हसीना को कहीं और शिफ्ट कर सकता है, लेकिन प्रत्यर्पण नहीं।भारतके शेख हसीना को प्रत्यर्पण करने की संभावना बहुत कम है,भले ही आईसीटी का फैसला कूटनीतिक दबाव बढ़ाए। 2013 की भारत-बांग्लादेश प्रत्यर्पण संधि के तहत हत्या जैसे अपराध प्रत्यर्पण योग्य है, लेकिन राजनीतिक अपराधों को छूट मिल सकती है।संधि के अनुछेद 8 के अनुसार, अगर आरोप अछे विश्वास में न्याय के हित में न लगें, तो प्रत्यर्पण अस्वीकार किया जा सकता है। सरकार हसीना को लंबे समय से करीबी सहयोगी मानती रही है,और उनकी निर्वासन स्थिति को राजनीतिक शरण के रूप में देखा जा रहा है। आईसीटी का फैसला बांग्लादेश के कानून के तहत अंतिम और बाध्यकारी है,लेकिन अपील के सीमित गुंजाइश है।आईसीटी एक्ट1973 के अनुसार,दोषी को सुप्रीम कोर्ट की अपीलीय खंडपीठ में 30 दिनों के अंदर अपील दायर करने का अधिकार है, जिसका फैसला 60 दिनों में होना चाहिए। लेकिन हसीना की अनुपस्थिति में ट्रायल चला,इसलिए अपील के लिए सरेंडर या गिरफ्तारी जरूरी। अगर अपील खारिज हुई, तो सजा निष्पादित हो सकती है।हसीना के वकीलों ने संयुक्त राष्ट्र को अपील भेजी है,जिसमें ट्रायल को राजनीतिक बदले की कार्रवाई कहा गया, लेकिन यूएन का हस्तक्षेप बाध्यकारी नहीं।अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फैसला मान्य है, लेकिन भारत जैसे देशों पर प्रत्यर्पण के लिए केवल दबाव बनाता है, बाध्य नहीं करता। हसीना ने फैसले को कंगारू कोर्ट कहा है। साथियों बातें कर हम प्रत्यर्पण संधि का कानूनी ढांचा और भारत -बांग्लादेश प्रत्यर्पण संधि के अनुछेद 6 तथा 8 को समझने की करें तो भारत और बांग्लादेश के बीच 28 जनवरी 2013 को प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर हुए, जिसे दोनों देशों ने बाद में क्रमशः स्वीकृति दी।यह संधि आपराधिक अपराधों के संदर्भ में पारस्परिक प्रत्यर्पण की व्यवस्था करती है, जिसमेंदोहरी आपराधिकता (ड्यूलक्रिमिनलिटी) भी शामिल है,अर्थात् जिस अपराध के लिए प्रत्यर्पण माँगा जा रहा है,वह दोनों देशों की कानून व्यवस्था में आपराधिक होना चाहिए। संधि की विशेष प्रावधानों में, अनुछेद 6 (राजनीतिक अपराध अपवाद) और अनुछेद 8 दोनों अहम 'रक्षा तंत्र' (सर्फगार्ड्स) प्रदान करते हैं,जिन्हें भारतीय पक्ष उपयोग कर सकता है। अनुछेद 6 कहता है कि प्रत्यर्पण को मना किया जा सकता है यदि वह अपराध राजनीतिक प्रकृति का हो। अनुछेद 8 में और भी विस्तृत आधार दिए गए हैं उदाहरण के लिए, प्रत्यर्पण अनुरोध को यह जांचने का अधिकार है कि वह इच्छाशक्ति (गुड फेथ) में किया गया है या न्याय के हित में किया गया है या नहीं; यदि अभियोग न्याय के इरादे से न हो,अथवा यदि अभियुक्त को निष्पक्ष सुनवाई का खतरा हो, या उनकी जान को खतरा हो,तो प्रत्यर्पण से इनकार किया जा सकता है। साथियों बात अगर हम नवीनतम विश्लेषणों के अनुसार, अनुछेद 8 (3) को समझने की करें तो, विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो सकता है क्योंकि यह आरोपों की उत्पत्ति की प्रकृति पर सवाल उठाने की अनुमति देता है,यदि अनुरोध स्वीकार किए जाने योग्य नहीं लगता, या वह न सिर्फ अपराध की आईना नहीं बल्कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता की बुनियाद पर है, तो प्रत्यर्पण को ठुकराया जा सकता है। इसलिए, प्रत्यर्पण संधि में यह स्पष्ट कानूनी छूट मौजूद है,यानी भारत को यह विकल्प मिला है कि वह मांग को पूरी तरहस्वीकार न करे, यदि वह यह ठहरे कि मामला राजनीतिक है, या अनुरोध इच्छाशक्ति या उचित न्याय के संदर्भ में पर्याप्त सटीक नहीं है। साथियों बात अगर हम शेख हसीना का मामला,इसकीकानूनी और राजनीतिक विश्लेषण की दृष्टि से समझने की करें तो,यह स्पष्ट रूप से न सिर्फ कानूनी, बल्कि राजनीतिक तनाव का कहानी है-(1)आईसीटी -बीडी ने शेख हसीना को मौत की सज़ा सुनाई है। यह फैसला गंभीर है, क्योंकि मृत्यु दंड एक ऐसा परिणाम है जिसे प्रत्यर्पित देश (यहां भारत) गंभीरता से मापेगा, खासकर यह देखते हुए कि प्रत्यर्पण स्वेच्छा का नहीं, बल्कि संवैधानिक कानूनी साझेदारी के ढांचे में हो रहा है।खबरों के मुताबिक, ट्रिब्यूनल ने उन घटनाओं का हवाला दिया है जिनमें छात्रों पर हिंसा, बमबारी, मेडिकल ट्रीटमेंट में व्यवधान आदि शामिल हैं। (2)भारत की प्रतिक्रिया- मीडिया में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत ने बहुत सावधान बयान दिया है उसने बांग्लादेश में शांति, लोकतंत्र, स्थिरता और समावेशिता का समर्थन व्यक्त किया है, सभी पक्षों से संवाद करने की इच्छा जताई है, लेकिन एक स्टीक हाँ, प्रत्यर्पण करेंगे या नहीं कहने से बचा है। यह स्पष्ट संकेत है कि भारत कानूनी और राजनीतिक दोनों दृष्टिकोणों को जोड़ते हुए आगे बढ़ना चाहता है। (3) संवैधानिक आधारों से भारत का फायदा-भारत के पास दो बड़े हथियार हैं (अ) अगर मुकदमा राजनीतिक प्रेरित है (अनुछेद 6 के अंतर्गत), और (ब) अगर मुकदमा ईमानदारी (गुड फेथ) और न्याय के हित में नहीं है (अनुछेद 8)। ये दोनों प्रावधान भारत को कानूनी आधार देते हैं, ताकि वह प्रत्यर्पण अनुरोध को ठुकरा सके, यदि वह यह ठहरे कि मामला सिर्फ राजनैतिक नफे-नुकसान की लड़ाई है, न कि निष्पक्ष, स्वतंत्र और पारदर्शी न्याय की प्रक्रिया।(4) सुरक्षा और निष्पक्ष सुनवाई का जोखिम- भारत यह भी देख सकता है कि यदि हसीना को वापस भेजा गया, तो क्या उन्हें बांग्लादेश में असुरक्षित स्थिति का सामना करना पड़ सकता है? क्या ट्रिब्यूनल ने न्यायिक स्वतंत्रता का उल्लंघन किया है? क्या उनके विरुद्ध अभियोजन एकतरफा है? यदि भारत यह महसूस करता है कि हसीना कोनिष्पक्ष सुनवाई का खतरा है, या कि उनकी जान, उनकी सुरक्षा, या उनकी अपील प्रक्रिया को सही तरह से नहीं मान लिया जाएगा, तो यह एक मजबूत आधार हो सकता है प्रत्यर्पण से इनकार करने का। (5)हसीना का स्वयं का विकल्प- हसीना के पास कानूनी रास्ते भी हैं वह बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ अपील कर सकती है। हालांकि, उसके लिए उन्हें वहाँ जाना होगा,और इसलिए यह एक जटिल कदम होगा। यह अपने आप में एक बड़ा खतरा हो सकता है, क्योंकि वापसी करना मतलब जान-अपील - सुरक्षा जोखिमों को स्वीकार करना (6) राजनीतिक पृष्ठभूमि - हसीना भारत में 5 अगस्त 2024 से है, उसी दिन बांग्लादेश में तख्तापलट हुआ था। यह पृष्ठभूमि बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह दर्शाती है कि उनकी अनुपस्थिति कानूनी मसले केवलमात्र राजनीतिक सत्ता परिवर्तन से जुड़े हुई है। यह वह बिंदु है जहाँ भारत को यह देखना होगा कि यह मामला सिर्फ वांछित प्रत्यर्पण अनुरोध नहीं है,बल्कि व्यापकअनुरोध और क्षेत्रीय राजनीतिक परिदृश्य में फिट बैठता है। साथियों बातें अगर हम भारत के विकल्प और रणनीतिक विचार को समझने की करें तो,इन कानूनी और राजनीतिक फैक्टर्स के मद्देनजर, भारत के सामने कुछ प्रमुख विकल्प हैं? (1)प्रत्यर्पण से इनकार करना- भारतअनुछेद 8 का उपयोग कर सकता है और कह सकता है कि बांग्लादेश की मांग न्याय के हित मेंइच्छाशक्ति में नहीं दी गई है, बल्कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण की गई है।

सम्पादकीय...

महिला श्रमिक

वैश्विक स्तर पर बढ़ती आर्थिक अनिश्चितता के बीच भारत की नई श्रम संहिताओं का कार्यान्वयन घरेलू लचीलेपन को मजबूत करने और समावेशी विकास को आगे बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण मौका है। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करना न केवल मैन्युफैक्चरिंग या तकनीकी क्षमता का विस्तार, बल्कि समावेशी एवं सुदृढ़ संस्थानों के निर्माण पर भी निर्भर करेगा। सच्ची आत्मनिर्भरता एक ऐसी अर्थव्यवस्था के निर्माण में निहित है जहां प्रत्येक नागरिक, विशेषकर महिलाएं देश की विकास गाथा में सार्थक रूप से भाग ले सकें। भारत ने इस दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) 2023-24 के अनुसार, 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं का श्रमिक जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) 2017-18 में 22.0 प्रतिशत से बढ़कर 40.3 प्रतिशत हो गया है। जबकि, इसी अवधि में श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) 23.3 प्रतिशत से बढ़कर 41.7 प्रतिशत हो गई है। ये आंकड़े श्रम बाजार में भागीदारी के मामले में व्याप्त लैंगिक अंतर में आई उल्लेखनीय कमी को दर्शाते हैं तथा व्यापक आर्थिक समावेशन की दिशा में सकारात्मक बदलाव की ओर भी इशारा करते हैं। फिर भी महिलाओं का एक बड़ा हिस्सा श्रमबल से बाहर है और जो महिलाएं कार्यरत हैं भी, उनमें से कई उन अनौपचारिक क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं जहां उन्हें कम वेतन, नौकरी की सीमित सुरक्षा और न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा की समस्या से जूझना पड़ रहा है। कृषि एवं घरेलू काम से लेकर घर-आधारित उद्यमों और गिग प्लेटफॉर्म तक, अनौपचारिक रोजगार अवसर नाजुक आर्थिक स्थिति और असमानता को मजबूत करता है। इस संदर्भ में भारत के श्रम कानूनों को हाल ही में चार व्यापक संहिताओं में संहिताबद्ध किया जाना इन कमियों को दूर करने का एक अनूठा मौका है। औपचारिकीकरण, संरक्षण और समान पहुंच पर ध्यान केन्द्रित करके इन सुधारों का उद्देश्य अपेक्षाकृत अधिक समावेशी और सुदृढ़ श्रम बाजार की नींव रखना है। इस प्रयास में भारत अकेला नहीं है। वियतनाम, इंडोनेशिया, मिस्र और मैक्सिको सहित कई विकासशील देशों ने महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से श्रम कानूनों में महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। इनमें मातृत्व संबंधी लाभ का विस्तार करना तथा स्वैच्छिक सहमति, सुरक्षित परिवहन, पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था, महिला पर्यवेक्षण एवं उत्पीड़न-विरोधी ठोस सुरक्षा जैसे सुरक्षात्मक उपायों के तहत महिलाओं को रात्रि पाली में काम करने की अनुमति देना शामिल है। ऐसे उपाय सिर्फ रोजगार को ही संभव बनाने से जुड़े नहीं हैं, बल्कि इनका जुड़ाव महिलाओं की गरिमा, स्वायत्तता और आर्थिक प्रगति में समान हिस्सेदारी सुनिश्चित करने से भी है। वेतन और कामकाज की स्थितियों में लिंग-आधारित भेदभाव की समाप्ति : भारत के श्रम सुधार, विशेष रूप से वेतन संहिता (2019) और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएं संहिता, 2020 का उद्देश्य वेतन तथा कामकाज की स्थितियों में लंबे समय से चले आ रहे और श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी को सीधे प्रभावित करने वाले लिंग-आधारित भेदभाव से निपटना है। वेतन संहिता (2019) भर्ती और वेतन में लिंग-आधारित भेदभाव को स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित करके समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत को सुदृढ़ करती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह संहिता संगठित और असंगठित, दोनों क्षेत्रों में न्यूनतम वेतन कवरेज को सार्वभौमिक बनाती है। श्रम बाजार में महिलाओं की कार्य क्षमता को प्रभावित करने वाला एक अन्य प्रमुख कारक उन पर काम का दोहरा बोझ है। इस बोझ के तहत उन्हें वेतनभोगी काम के साथ-साथ घरेलू एवं बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बिठाना पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुमानों के अनुसार, 2023 में 74.8 करोड़ लोग (15 वर्ष या उससे अधिक आयु के) देखभाल संबंधी जिम्मेदारियों के कारण वैश्विक श्रमबल का हिस्सा बनने में असमर्थ थे। इनमें अधिकांश महिलाएं थीं। इसके अलावा, महिलाओं के अनुकूल एक ऐसे बुनियादी ढांचे की जरूरत है जो कार्यस्थल पर लैंगिक दृष्टि से महिलाओं और पुरुषों की भिन्न-भिन्न प्रकार की विशेष जरूरतों को पूरा कर सके। व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएं संहिता सभी क्षेत्रों में स्वास्थ्य, स्वच्छता, शौचालय और शिशुगृह संबंधी सुविधाओं के लिए न्यूनतम मानक स्थापित करती है। यह प्रावधान लंबे समय से चली आ रही बुनियादी ढांचे की उन कमियों को दूर करता है, जिसने महिलाओं को विशेष रूप से मैन्युफैक्चरिंग, खनन और निर्माण क्षेत्रों में रोजगार पाने से रोका है। यह एक हद तक लचीलापन लाता है जो विशेष रूप से सेवा और ज्ञान-आधारित पेशों में महिलाओं को भुगतान किए गए काम और देखभाल की जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बिठाने में और अधिक सहायता कर सकता है। आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने हेतु आत्मनिर्भर महिलाओं के उत्थान को भी बढ़ावा देना होगा और उन्हें एक सशक्त, आत्मनिर्भर एवं प्रगतिशील बनाने वाले श्रम इकोसिस्टम द्वारा संरक्षित करना होगा। चाहे महिलाएं खेतों पर हों, कारखानों में हों, गिग प्लेटफॉर्म पर या छोटे उद्यमों में हों, उन्हें सिर्फ विकास के लाभार्थी के रूप में ही नहीं बल्कि इसके शिल्पी के रूप में भी पहचानना होगा।

श्रम संहिताओं को अब पूरी तरह से लागू करना महज सामाजिक न्याय का मामला नहीं है, बल्कि एक रणनीतिक अनिवार्यता भी है। यह कदम एक ऐसे सुदृढ़, प्रतिस्पर्धी और समावेशी अर्थव्यवस्था की नींव रखेगा जो वास्तव में आत्मनिर्भरता की भावना का प्रसार करेगा और भारत को दीर्घकालिक समृद्धि की ओर अग्रसर करेगा।

क्या चुनाव बॉयकॉट की नौबत आ पहुंची है?

बिहार चुनाव के परिणाम के बाद बहुत साथियों ने मुझसे यह सवाल पूछा - अब चुनाव लड़ने का मतलब ही क्या बचा है? अगर हर चुनाव में ले देकर भाजपा को ही जिताया जाएगा और विपक्ष का सूपड़ा साफ ही किया जाएगा, तो ऐसे चुनाव में हिस्सा लेकर उसे वैधता प्रदान करने का क्या फायदा? क्यों नहीं विपक्ष चुनावों का बॉयकॉट ही कर देता? मैं उनकी राय से सहमत नहीं था। लेकिन उनके सवाल गंभीर हैं। सवाल पूछने वाले अधिकांश सामान्य नागरिक, बुद्धिजीवी या फिर कार्यकर्ता हैं, जो किसी दल से नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था और मर्यादा से जुड़े हैं, जो हमारे गणतंत्र के भविष्य के बारे में उद्वेलित हैं। यह सवाल किसी खाली दिमाग की खुराफाती उपज नहीं है। हमारे लोकतंत्र का लगातार होता क्षय इन लोगों को ऐसे सवाल पूछने पर मजबूर करता है। दुनिया की कई अन्य स्थापित लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की तरह भारत भी अब ऐसे मुकाम पर पहुंच गया है कि इसे सामान्य लोकतंत्र या कमीबेशी वाला लोकतंत्र भी नहीं कहा जा सकता। यह पुरानी तर्ज वाली तानाशाही भी नहीं है, जिसमें मार्शल लॉ और सैंसरशिप होती थी। 21वीं सदी में अधिनायकवाद का एक नया मॉडल उभरा है, जहां लोकतांत्रिक व्यवस्था की संस्था, मर्यादा और परिपाटी को चौपट कर दिया जाता है लेकिन चुनाव की रस्म बरकरार रखी जाती है। सत्ता को जनता का समर्थन हासिल है, यह दिखाने की मजबूरी चुनावी प्रतिस्पर्धा को जिंदा रखती है। चुनाव विपक्षी दलों के लिए बाधा-दौड़ के समान होता है, जहां उन्हें कदम-कदम पर किसी अड़चन या फिसलन का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर वे इसे पार कर लें तो चुनाव जीत भी सकते हैं। जनता-जनार्दन के अनुमोदन की जरूरत के चलते यह सुनिश्चित करना पड़ता है कि चुनाव एकदम स्वांग न बन जाए, उन्हें जनमत के आईने की तरह पेश किया जा सके। सरकार के विरोधियों के लिए कोई भी चुनाव जीतना टेढ़ी खीर है, मगर असंभव नहीं। इस हालात में किसी न किसी मोड़ पर यह सवाल सिर उठाता है - इस बाधा-दौड़ में शामिल होने की क्या तुक है? चुनाव का बॉयकॉट कर क्यों नहीं अधिनायकवादी सत्ता पर जनसमर्थन की मुहर लगाने की इस रस्म का पर्दाफाश किया जाए? इस सवाल का जवाब आसान नहीं है। चूंकि चुनाव करवाने का सारा खेल वैधता हासिल करने का है, इसलिए असली मुद्दा यह है कि ऐसे किसी फैसले को जनता कैसे देखेगी। इसे फिक्स्ड मैच को खारिज करने की तरह देखा जाएगा या फिर हारे हुए खिलाड़ी द्वारा पलायन की तरह। इसलिए ऐसे किसी भी फैसले को दो कसौटियों पर कसना होगा। पहली, क्या इस बाधा-दौड़ में जीतने के लिए हर संभव प्रयास हो चुका है? क्या जनता देख रही है कि जनसमर्थन हासिल करने के लिए जो कुछ संभव था, वह विपक्ष सफलतापूर्वक कर चुका है? दूसरा, क्या यह साफ है कि चुनाव परिणाम में धांधली हुई है? क्या जनता समझ रही है कि चुनाव परिणाम जनता की सच्ची भावना का प्रतिनिधित्व नहीं करते? बिहार का चुनाव इन दोनों कसौटियों पर पूरी तरह खरा नहीं उतरता। यानी बिहार चुनाव के आधार पर चुनाव के बॉयकॉट की मांग सही नहीं जान पड़ती। पहले विपक्षी महागठबंधन की चुनावी तैयारी और चुनाव प्रचार को लें। बिहार की राजनीति का जानकार हर शख्स यह जानता है कि विपक्ष के सामने काफी लंबे समय से दो बुनियादी चुनौतियां हैं। एक तो महागठबंधन के मुकाबले एन.डी.ए. का सामाजिक समीकरण ज्यादा मजबूत है। महागठबंधन मुस्लिम-यादव के पक्के तथा रविदास और मल्लाह समाज जैसी जातियों के कच्चे समर्थन पर टिका है जो कुल मिलाकर बिहार के 40-42 प्रतिशत है।

उधर एन.डी.ए. के पक्ष में अगड़ी जातियों के अलावा कुर्मी, कुशवाहा, पासवान और बड़ी मात्रा में हिंदू अति-पिछड़े भी लामबंद है, जिनकी आबादी 50 प्रतिशत से ज्यादा है। चुनाव जीतने के लिए विपक्ष की पहली जिम्मेदारी थी कि वह पिछड़े-दलित-हाशियाग्रस्त समाज और गरीब-गुरबा को एक माला में पिरोने की कोशिश करता और अपने सामाजिक गठबंधन का विस्तार करता। किंतु वह ऐसा नहीं कर पाया।

दूसरी तरफ विपक्ष के सामने आर.जे.डी. शासन पर 'जंगल राज' के दाग को मिटाने और प्रदेश के समक्ष एक सार्थक एजैंडा रखने की चुनौती थी। इस मायने में भी महागठबंधन कुछ ठोस और बड़ा नहीं कर पाया। उधर नीतीश कुमार सरकार ने पिछले कई चुनाव से महिलाओं को अपनी तरफ झुकाने की कोशिश जारी रखी और महिलाओं के साथ अन्य अनेक वर्गों को चुनाव से पहले पैंशन वृद्धि, मानदेय में बढ़ोतरी और बिजली बिल में कटौती जैसी सौगात देकर अपना पाला मजबूत किया। ऐसे में एन.डी.ए. का जीतना बहुत हैरानी की बात नहीं थी। ऐसे चुनाव के आधार पर चुनाव बॉयकॉट की बात करना बिहार की जनता के गले नहीं उतरेगा। बिहार चुनाव के दौरान और उसके बाद चुनाव में धांधली की बहुत शिकायतें आईं। इसमें कोई शक नहीं कि बिहार चुनाव व्यवस्थागत बेईमानी का नमूना था। निर्वाचन सूची से 68 लाख नाम निकालना और 24 लाख नाम जोड़ना, आचार संहिता लागू होने के बाद महिलाओं को 10,000 रुपए घूस देने की अनुमति देना, उन्हीं 'जीविका दीदियों' को चुनाव ड्यूटी देना, भाजपा समर्थकों के लिए अन्य राज्यों से बिहार के लिए विशेष ट्रेन चलवाना, मीडिया का दिन-रात एन.डी.ए. के लिए प्रचार और महागठबंधन के विरुद्ध विषवमन - ये चंद उदाहरण व्यवस्थागत भेदभाव को साबित करने के लिए पर्याप्त हैं। शुरू से आखिर तक चुनाव महागठबंधन के लिए बाधा-दौड़ था। लेकिन फिलहाल एक न्यूनतम अर्थ में चुनावी धांधली के पक्के प्रमाण नहीं हैं।

यानी बिहार में इसकी शिकायत तो आई है कि वोट में धांधली हुई, मतदान के आंकड़े बढ़ाए गए और सीटों की संख्या में आश्चर्यजनक बढ़ोतरी हुई, लेकिन इसके पुख्ता सबूत नहीं हैं। ऐसे संवेदनशील सवाल पर बिना सबूत के दावा करना ठीक नहीं है। बाद में और प्रमाण मिल जाएं तो बात अलग है। फिलहाल महागठबंधन के पक्के समर्थकों के अलावा बहुत लोग यह मानने को तैयार नहीं होंगे कि एन.डी.ए. ने चोरी के आधार पर सरकार बनाई है। अभी की स्थिति में बिहार चुनाव के आधार पर वोट बॉयकॉट की मांग करने से भेड़िया वाली कहानी दोहराए जाने की आशंका है - जब भेड़िया सचमुच आएगा तो कोई यकीन करने को तैयार नहीं होगा।

वंदे मातरम् केवल उद्घोष नहीं दुनिया के शीर्ष 10 गीतों में सर्वाधिक लोकप्रिय दूसरा गीत

बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बंगाल के कांतलपाड़ा गांव में जब 7 नवंबर, 1876 में वंदे मातरम् गीत की रचना की तब उनके मानस में शायद ही यह होगा कि यह गीत स्वतंत्रता आंदोलन में आजादी के दिवानों का प्रेरक होने के साथ ही आजादी के बाद भी देश की राष्ट्रीय एकता और मातृभूमि के प्रति प्रेम और श्रृद्धा का प्रतीक बन जाएगा। वंदे मातरम् में जिस तरह से माँ भारती की स्तुति की गई है वह हमारी पहचान और गौरवपूर्ण सांस्कृतिक विरासत से रुबरू कराने का माध्यम बन गई। 1870 के भयंकर अकाल और अंग्रेजों द्वारा महारानी की शान में गॉड सेव क्वीन के लिए बाध्य करने की प्रतिक्रिया के रुप में वंदे मातरम् की आधार भूमि तैयार हुई। कुछ समय बाद ही बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास आनंद मठ में वंदे मातरम् को प्रमुख स्थान दिया गया। आनंद मठ भी गुलामी से मुक्ति और अंग्रेजों के प्रति विद्रोह की भावना से ओतप्रोत उपन्यास होने से आजादी के आंदोलन ही नहीं आज भी प्रेरणा का स्रोत है। आनंद मठ में भवानन्द संन्यासी संन्यासी विद्रोहियों का नेतृत्व करते हुए यह गीत गाते हैं। वंदे मातरम् गीत की गंभीरता को इसी से समझा जा सकता है कि गुरुवर रविन्द्र नाथ टैगोर ने 1896 के कांग्रेस के सम्मेलन में इसे अपने स्वर देते हुए स्वयं गाया। उसके बाद तो वंदे मातरम् भारत की आत्मा ही बन गया। स्वतंत्रता आंदोलन के सेनानियों के लिए तो वंदे मातरम् जयघोष ही बन गया। 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध का मार्च गीत ही वंदे मातरम् रहा। हालांकि वंदे मातरम् को लेकर मुस्लिम लीग आदि ने सांप्रदायिकता, धर्म विशेष से प्रेरित और मां दुर्गा को लेकर विरोध व्यक्त किया गया और यही कारण रहा कि वंदे मातरम् गीत के आरंभिक दो छंदों को ही कांग्रेस द्वारा राष्ट्रगीत के रुप में स्वीकारा गया। यह हमारे लिए गौरव की बात है कि आजादी के अमृत काल में हम वंदे मातरम् के 150 वें वर्ष को मनाने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले दिनों मन की बात में देशवासियों से संवाद कायम करते हुए वंदे मातरम् के 150 वें वर्ष पर आयोजनों की श्रृंखला के माध्यम से आज की पीढ़ी को वंदे मातरम् के इतिहास और प्रेरकता से रुबरू कराने का संदेश दिया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि वंदे मातरम् भले ही 19 वीं शताब्दी में लिखा गया था लेकिन इसकी भावना भारत के हजारों वर्ष पुरानी अमर चेतना से जुड़ी थी। वेदों में जिस भाव से माता भूमि पुत्रो अहम् पृथिव्या भाव से जुड़ा है। 1950 में वंदे मातरम् को राष्ट्रीय गीत के रुप में अपनाया गया। 1950 में ही जदुनाथ भट्टाचार्य ने वंदे मातरम् को संगीत दिया। जनगणमन जहां राष्ट्रगान है और औपचारिक आयोजनों में राष्ट्रगान को गाया जाता है और उसके अपने प्रोटोकाल है वहीं राष्ट्रगीत किसी भी राष्ट्रीय अवसर पर गाया जा सकता है। वंदे मातरम् केवल गीत या उद्घोष ना होकर 140 करोड़ देशवासियों को एकजुट करने, राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत करने और सनातन भारतीय संस्कृति से रुबरू कराने का माध्यम है। भारत भूमि की सनातन सांस्कृतिक विरासत से रुबरू कराने का माध्यम है वंदे मातरम् गुलामी के दौर में वंदे मातरम् राष्ट्रीय भावना, देश प्रेम और स्वतंत्रता आंदोलन का उद्घोष रहा है तो आजादी के बाद यह देशवासियों की आत्मा बन चुका है।

विकसित भारत 2047 : अन्नदाता की अनदेखी नहीं कर सकते

2047 तक 'विकसित भारत' का लक्ष्य एक बुनियादी सवाल खड़ा करता है कि जब देश आजादी का शताब्दी वर्ष मना रहा होगा, तब हमारे किसानों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति कैसी होगी? बीते तीन दशकों से हर वेतन आयोग के साथ सरकारी कर्मचारियों के वेतन-पैंशन में इजाफा देश की बढ़ती आर्थिक ताकत एवं बेहतर जीवनस्तर को दर्शाता है। लेकिन इसके ठीक उलट एक साधारण किसान की आमदनी बढ़ती महंगाई व खेती पर बढ़ती लागत के कारण पिछड़ रही है। नैशनल सैंपल सर्वे आर्गेनाइजेशन (एन.एस.एस.ओ.) के मुताबिक, खेती से जुड़े एक परिवार की मासिक औसत आमदनी मात्र 10,218 रुपए है, जो एक सरकारी कर्मचारी की शुरुआती तनख्वाह के एक चौथाई से भी कम है। आमदनी में गहराती यह खाई केवल किसानों की आर्थिक समस्या नहीं, बल्कि यह एक गंभीर चेतावनी है। इसे अभी नहीं सुलझाया गया, तो हमें दो अलग भारत देखने को मिलेंगे। एक शहरों में चमकता 'विकसित भारत' व दूसरा गांवों में संघर्ष करता 'वंचित भारत'।

खेती से आमदनी गुजारे लायक भी नहीं - भारत की 42 प्रतिशत से अधिक आबादी खेती पर निर्भर है, लेकिन देश की जी.डी.पी. में योगदान 15 प्रतिशत पर अटका है। यह बड़ा अंतर दर्शाता है कि खेती में प्रोडक्टिविटी एवं वैल्यू एडिशन जरूरत मुताबिक नहीं हो रहा। खेती सैक्टर में आधुनिक टैक्नोलॉजी के लिए जी.डी.पी. का मात्र 0.4 प्रतिशत ही आर. एंड डी. पर खर्च हो रहा है, जबकि विकसित देश 1 से 3 प्रतिशत तक निवेश करते हैं। जमीन व जल जैसे प्राकृतिक संसाधन सीमित हैं, औसत खेत के आकार घटकर 1.08 हैक्टेयर रह गए हैं। ऐसे में इनोवेशन आधारित उत्पादकता बढ़ाए बगैर किसान मुश्किल से गुजारे भर की आमदनी पर अटके रहेंगे, जबकि बाकी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ती जाएगी।

सबसिडी से प्रोडक्टिविटी की ओर - भारत की मौजूदा कृषि नीति का जोर इनपुट सबसिडियों पर है। फर्टिलाइजर, बिजली, सिंचाई, पी.एम. किसान सम्मान निधि, पी.एम. फसल बीमा योजना व अनाज की सरकारी खरीद पर सालाना 4 लाख करोड़ से ज्यादा खर्च के बावजूद ये योजनाएं प्रोडक्टिविटी व टिकाऊ विकास सुनिश्चित नहीं कर पाई। 4 लाख करोड़ का एक-तिहाई भी आर. एंड डी., कृषि विस्तार सेवाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगाया जाए तो परिणाम बेहतर होंगे।

टैक्नोलॉजी की क्रांति अभी अधूरी दुनिया के प्रमुख कृषि देश सबसिडी के दम पर नहीं, बल्कि साइंस-टैक्नोलॉजी व संस्थागत सुधारों के कारण समृद्ध हुए हैं। इसराईल ने मरुस्थल में भी सटीक सिंचाई व जल दक्षता के मॉडल से दुनिया की अगुवाई की। हरियाणा से भी छोटा नीदरलैंड्स दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कृषि उत्पाद निर्यातक देश बना।

इसका श्रेय बड़े पैमाने पर कृषि अनुसंधान, डाटा आधारित खेती व उन्नत ग्रीनहाऊस टैक्नोलॉजी को जाता है। चीन ने भी अनुसंधान एवं डिजिटल विस्तार सेवाओं के जरिए ग्रामीण व शहरी आबादी की आमदनी के बीच की खाई कम की है। भारत की एग्री-टैक व्यवस्था अब ड्रोन स्प्रेइंग, मिट्टी मानचित्रण, फार्म-गेट लॉजिस्टिक्स व डिजिटल मंडियों वाले स्टार्टअप्स की दिशा में बढ़ रही है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर और पी.एम. किसान ड्रोन योजना का बड़े पैमाने पर विस्तार हो रहा है।

मील के पत्थर साबित हुए देशों से सबक - 1960 के दशक में जब जापान ने विकास की छलांग लगाई, तो उसकी बुनियाद ग्रामीण इलाकों के आधुनिकीकरण, सर्वसाक्षरता, ग्रामीण सहकारी समितियों और खेती के मशीनीकरण पर टिकी थी। दक्षिण कोरिया ने 1970 के दशक में 'सायमुल आंदोलन' के जरिए गांवों को मजबूत बनाकर औद्योगिक क्रांति की नींव रखी। 'विकसित भारत' का लक्ष्य हासिल करने के लिए ग्रामीण भारत को केवल लाभार्थी नहीं, बल्कि विकास का भागीदार बनाना होगा।

खेती के हालात बदलने को चार अहम कदम- पहला, राष्ट्रीय फसल क्षति मुआवजा कोष।

फसल बीमा क्लेम की धीमी व विवादित प्रक्रिया के बदले एक पारदर्शी जिला-स्तरीय कोष के जरिए किसानों को बाढ़, सूखे या कीट हमलों की स्थिति में तुरंत राहत दी जा सकती है। पी.एम. फसल बीमा योजना करीब 5 करोड़ किसानों को कवर करती है, पर क्लेम में देरी एवं प्रीमियम विवादों ने ऐसी योजनाओं पर किसानों का भरोसा कमजोर किया है। एक समर्पित एवं असरदार फसल मुआवजा सिस्टम भरोसे को कायम कर सकता है। दूसरा, कृषि अनुसंधान में निवेश।

कृषि अनुसंधान का 9,000 करोड़ रुपए का बजट इनोवेशन के लिए जरूरी राशि का आधा भी नहीं।

इस निवेश को देश की जी.डी.पी. के 1 प्रतिशत तक बढ़ाया जाए, तो सूखा-रोधी फसलों की किस्में, बायो-फर्टिलाइजर, जलवायु सहनशील बीज व बेहतर भंडारण जैसे इनोवेशन संभव होंगे। कृषि विज्ञान केंद्रों को रियल-टाइम डिजिटल सलाह सेवाओं से जोड़कर सीधे किसानों के स्मार्टफोन तक पहुंचाया जा सकता है।

तीसरा, संस्थागत एवं बाजार सुधार। किसान उत्पादक संगठनों (एफ.पी.ओ.) को मजबूत बाजार लिंक मिले, कांट्रैक्ट फार्मिंग में निवेश सुरक्षा का प्रावधान हो, वेयरहाऊस रसीद के जरिए बैंकों से किसानों को सस्ता कर्ज मिले तो किसान बढ़े दाम पर फसलें बेच सकेंगे। 'ई-नेम' मार्केट पोर्टल को 'इंटरऑपरेबल' मंच बनाया जाए, ताकि किसान अपनी उपज देशभर में कहीं भी व विदेशों में बेच सकें। चौथा, जलवायु परिवर्तन से मुकाबला। 2047 तक कृषि को नए जलवायु जोखिमों का सामना करना होगा। विश्व बैंक के अनुसार, जलवायु बदलाव के कारण कृषि आय 15 से 18 प्रतिशत तक घट सकती है। भारत की 55 प्रतिशत से अधिक खेती वर्षा पर निर्भर है पर बिगड़ा मानसून चक्र खेती के लिए खतरे की घंटी है। जी-20 में भारत की खाद्य सुरक्षा पहल के लिए आई.सी.ए.आर. व नासा के जलवायु डाटा सहयोग से इनोवेटिव समाधान किए जा सकते हैं।

समृद्धि की राह - भारत के विकास का रास्ता साफ है लेकिन यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण 'सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास' को हकीकत में लागू करने पर निर्भर करेगा। क्या विकसित भारत सबका भारत बनेगा, या दो अलग अर्थव्यवस्थाओं में बंटा भारत? 2047 के विकसित भारत की यात्रा में समृद्धि के सांझेदार अन्नदाता की अनदेखी नहीं की जा सकती।(लेखक कैबिनेट मंत्री रैंक में पंजाब इकोनॉमिक पॉलिसी एवं प्लानिंग बोर्ड के वाइस चेयरमैन भी हैं) डा. अमृत सागर मित्तल
(वाइस चेयरमैन सोनालीका)।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार भाटी ने कल्पना ऑफसेट प्रिन्टर्स, ई-9, [illegible] एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार भाटी, मो. : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। ([illegible])

रूसी तेल की खरीद को लेकर भारत पर अमेरिका का अतिरिक्त टैरिफ अनुचित, जीटीआरआई ने की तुरंत हटाने की मांग

नई दिल्ली। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव ने भारतीय वस्तुओं पर रूसी तेल श्रेणी के तहत लगाए गए 25फीसदी अतिरिक्त शुल्क को अनुचित करार देते हुए इसे तुरंत हटाने की मांग की है। जीटीआरआई का कहना है कि भारत ने रूस से कच्चे तेल की खरीद में भारी कमी कर दी है, इसके बाद इस दंडात्मक शुल्क का कोई मतलब नहीं रह गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी स्वीकार किया है कि भारत ने अब रूस से तेल खरीदना काफी हद तक बंद कर दिया है। उन्होंने 11 नवंबर को पुष्टि की कि अतिरिक्त शुल्क केवल भारत के पूर्व आयात को देखते हुए लगाया गया था और भरोसा दिलाया कि हम टैरिफ कम करने जा रहे हैं। जीटीआरआई ने कहा कि भारत ने अमेरिकी चिंताओं पर कार्रवाई की है, इसलिए अब वॉशिंगटन को बिना किसी देरी के इस शुल्क को हटाने के लिए कदम उठाना चाहिए, न कि इसे व्यापक, समय लेने वाली व्यापार वार्ताओं से जोड़ना चाहिए। इस स्तर पर टैरिफ को बरकरार रखना भारतीय निर्यातकों को दंडित करने और एक ऐसे साझेदार को अनुचित रूप से लक्षित करने के समान है, जो अमेरिकी ऊर्जा आपूर्तिकर्ताओं की ओर काफी हद तक स्थानांतरित हो चुका है। जीटीआरआई ने चेतावनी दी है कि इस उपाय को लंबा खींचने से सद्भावना कमजोर हो सकती है व चल रही व्यापार वार्ताओं में प्रगति धीमी हो सकती है। थिंक टैंक ने तर्क दिया कि शीघ्र वापसी से राष्ट्रपति ट्रम्प की प्रतिबद्धता का सम्मान होगा, भारत की अमेरिकी कच्चे तेल और एलपीजी की ओर तेजी से झुकाव को बढ़ावा मिलेगा, अमेरिकी ऊर्जा शिपमेंट को बढ़ावा मिलेगा, और द्विपक्षीय संबंधों में एक अड़चन दूर होगी। इससे अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं, खासकर चीन के साथ समानता बहाल हो जाएगी, जो तुलनात्मक दंड का सामना किए बिना बड़ी मात्रा में रूसी तेल खरीदना जारी रखे हुए हैं। व्यापार आंकड़े भारत की स्थिति का समर्थन करते हैं। अप्रैल और सितंबर 2025 के बीच, भारत का अमेरिकी पेट्रोलियम कच्चे तेल का आयात 66.9 प्रतिशत बढ़कर 5.7 अरब डॉलर हो गया। इससे भारत को कुल अमेरिकी पेट्रोलियम और उत्पाद निर्यात 36.3 प्रतिशत बढ़कर 7.5 अरब डॉलर हो गया। इसके विपरीत, अमेरिका को भारत का पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात 15 प्रतिशत घटकर 2.3 अरब डॉलर रह गया, जिससे पहले यह चिंता कम हो गई कि भारतीय रिफाइनरियां अमेरिकी बाजारों में दोबारा निर्यात के लिए रूसी कच्चे तेल का प्रसंस्करण कर रही हैं। भारत ने अमेरिका के साथ गहन ऊर्जा सहयोग का भी संकेत दिया है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) ने नवंबर और मार्च के बीच डिलीवरी के लिए 10 मिलियन बैरल यूएस मिडलैंड क्रूड का अनुबंध किया है। वहीं नई दिल्ली ने 2026 में लगभग 2.2 मिलियन टन अमेरिकी तरलीकृत पेट्रोलियम गैस के आयात के लिए अपने पहले संरचित सौदे को अंतिम रूप दिया है, जो देश की वार्षिक एलपीजी आवश्यकता का लगभग 10 प्रतिशत है। जीटीआरआई ने कहा कि भारत अब उन कुछ प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है, जो अमेरिका से तेल और एलपीजी की खरीद में उल्लेखनीय वृद्धि कर रही है।

एक नजर

गुरुग्राम हाउसिंग घोटालाः ईडी ने कारोबारी अमित कत्याल को किया गिरफ्तार, छह दिन की हिरासत में भेजा

नई दिल्ली। ईडी ने रीयल एस्टेट कारोबारी अमित कटियाल को मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें राजद प्रमुख लालू प्रसाद के परिवार का करीबी माना जाता है। अधिकारियों के मुताबिक, कत्याल को एजेंसी के गुरुग्राम क्षेत्रीय कार्यालय ने सोमवार को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत हिरासत में लिया। गुरुग्राम की एक विशेष अदालत ने उन्हें छह दिन के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया है। यह जांच गुरुग्राम के सेक्टर 70 में 14 एकड़ में बने क्रिश फ्लोरेंस एस्टेट में फ्लैटों की डिलीवरी न देने के आरोपों से संबंधित है। इस परियोजना का विकास कत्याल की कंपनी एंगल इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड कर रही थी। कत्याल को ईडी ने 2023 में रेलवे के कथित भूमि-के-लिए-नौकरी घोटाले से संबंधित एक अलग मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी गिरफ्तार किया था। इसमें लालू प्रसाद, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और परिवार के अन्य सदस्य शामिल थे। व्यवसायी को अगस्त में संघीय एजेंसी द्वारा क्रिश रियलटेक के माध्यम से घर खरीदारों से 500 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के तीसरे मामले में आरोप पत्र दाखिल किया गया था, जिसके वे प्रमोटर हैं।

यूएस शेयर बाजार में उथल-पुथलः एनवीडिया-बिटकॉइन की कीमतों में उछाल से चिंता, डाउ जोन्स और नैस्डैक का हाल जानिए

बिजनेस डेस्क। अमेरिकी शेयर बाजार में भारी उतार-चढ़ाव देखा गया। एशिया और यूरोप में हुई बिकवाली का असर वॉल स्ट्रीट पर भी दिखा। दिन की शुरुआत में S&P 500 में 1.5फीसदी की गिरावट दर्ज की गई। बाद में अधिकांश नुकसान की भरपाई हो गई और देर शाम केवल 0.2फीसदी की गिरावट दर्ज की गई। डाउ जोन्स का सूचकांक 0.6फीसदी गिरा, जबकि नैस्डैक ने 0.5फीसदी गोते लगाए। अमेरिका के अलावा एशिया और यूरोप के बाजारों में भी भारी गिरावट देखी गई। जापान का निक्केई 3.2फीसदी और दक्षिण कोरिया का कोस्पी 3.3फीसदी गिरा। France के सीसी 40 में भी 1.9 फीसदी की गिरावट दर्ज हुई। खबरों के मुताबिक मंगलवार को शेयर बाजार में सबसे बड़ा दबाव कंप्यूटर चिप्स बनाने वाली कंपनी- एनवीडिया के शेयर की कीमतों के कारण आया। शुरुआत में 1.4 फीसदी गिरावट के बाद सुबह इसमें 3.7% तक गिरावट भी देखी गई। इस महीने कुल गिरावट 10 फीसदी से अधिक हो चुकी है। आर्थिक मामलों और शेयर बाजार से जुड़े आंकड़ों के जानकार इसे वॉल स्ट्रीट की भाषा में करेक्शन बता रहे हैं। एनवीडिया के उतार-चढ़ाव का सीधा असर पूरे बाजार पर पड़ा, क्योंकि विशाल आकार के कारण ये कंपनी S&P 500 का सबसे प्रभावशाली स्टॉक है। एआई चिप्स की तेजी से बढ़ रही मांग के कारण हाल ही में कंपनी का बाजार मूल्य 5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। इस साल अप्रैल के बाद से अमेरिकी शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी देखी गई थी। राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से लगाए गए टैरिफों के बाद निवेशकों के उत्साह के बावजूद आलोचकों का मानना था कि यह तेजी बहुत असामान्य और असंतुलित रही है। विशेषकर एआई सेक्टर में एनवीडिया पिछले पांच साल में चार बार अपना मूल्य दोगुना कर चुकी है। एक अन्य कंपनी पैलेंटिर ने इस साल केवल छह महीनों में मूल्य दोगुना कर लिया। बाजार के मौजूदा हाल को लेकर बैंक ऑफ अमेरिका की तरफ से कराए गए सर्वे के अनुसार, बड़े निवेशकों का मानना है कि एआई सेक्टर आने वाले दिनों में तेजी से नीचे जा सकता है। हालांकि, 45फीसदी निवेशक एआई बबल को सबसे बड़ा संभावित जोखिम मानते हैं। चिंता यह भी है कि कंपनियां एआई और डेटा सेंटर्स में अत्यधिक निवेश कर रही हैं। ऐसी आशंका है कि भविष्य में इससे इसी तरह के लाभ की उम्मीद नहीं की जा सकती। एनवीडिया के अलावा अन्य हाई-फ्लाइंग सेक्टर भी मंगलवार के कारोबार के दौरान कमजोर दिखे। बिटकॉइन की कीमत सुबह 90,000 डॉलर से नीचे गई, जबकि पिछले महीने वह 125,000 डॉलर के करीब थी। बाद में यह थोड़ा बढ़कर 93,000 डॉलर के ऊपर पहुंची। अब बाजार की नजर बुधवार को आने वाली एनवीडिया की तिमाही रिपोर्ट पर है। इससे शेयरों की कीमत में गिरावट पर ब्रेक लग सकती है। कीमतों में उछाल की संभावना भी बरकरार है।

पीयूष गोयल 20-22 नवंबर को इस्राइल दौरे पर, व्यापार और रणनीतिक सहयोग को नई गति मिलने की उम्मीद

नई दिल्ली। केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल 20 से 22 नवंबर 2025 तक तीन दिवसीय आधिकारिक इस्राइल दौरे पर जाएंगे। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार, यह यात्रा इस्राइल के अर्थव्यवस्था और उद्योग मंत्री निर बरकात के निमंत्रण पर हो रही है। दौरे का उद्देश्य दोनों देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करना है। गोयल के साथ सीआईआई, फिक्की, एसोचैम और स्टार्ट-अप इंडिया से जुड़े 60 सदस्यीय व्यवसायिक प्रतिनिधिमंडल भी जाएगा, जो भारत-इस्राइल उद्योग सहयोग को नए स्तर पर ले जाने का संकेत है। गोयल बरकत और अन्य प्रमुख मंत्रियों सहित वरिष्ठ इस्राइली नेतृत्व के साथ उच्च-स्तरीय द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। चर्चाएं व्यापार और निवेश संबंधों को बढ़ावा देने और कृषि, जल, रक्षा, उभरती प्रौद्योगिकियों, जीवन विज्ञान, उन्नत विनिर्माण और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर केंद्रित होंगी। दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तावित भारत-इस्राइल मुक्त व्यापार समझौते की प्रगति की समीक्षा करने की भी उम्मीद है। इस यात्रा के दौरान, गोयल भारत-इस्राइल व्यापार मंच को संबोधित करेंगे, जिसमें दोनों देशों के प्रमुख व्यापारिक संगठन और उद्योग प्रतिनिधि एक साथ आएंगे। इस कार्यक्रम में पूर्ण सत्र, तकनीकी चर्चाएं और बी2बी बैठकें शामिल होंगी। इनका उद्देश्य निवेश को बढ़ावा देना, वाणिज्यिक संबंधों का विस्तार करना और संयुक्त उद्यम के अवसरों की खोज करना है। सीईओ फोरम का चौथा संस्करण भी आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा, मंत्री प्रमुख इस्राइली निवेशकों से मिलने के अलावा कृषि, विलवणीकरण, अपशिष्ट जल उपचार, साइबर सुरक्षा, स्मार्ट मोबिलिटी और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में काम करने वाली प्रमुख इस्राइली कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे। गोयल के कार्यक्रम में तेल अवीव के प्रमुख नवाचार केंद्रों और संस्थानों का दौरा भी शामिल है, जहां वे इस्राइल के तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र की जानकारी प्राप्त करेंगे। भारतीय प्रवासियों और भारतीय मूल के व्यापारिक नेताओं के साथ बातचीत सहित सांस्कृतिक और सामुदायिक कार्यक्रमों की भी योजना है।

सीमेंट परिवहन हुआ सस्ता, जानें रेलवे की किस पहल से मध्यमवर्गीय परिवारों को मिलेगी राहत

नई दिल्ली। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देशभर में सीमेंट परिवहन लागत कम करने के उद्देश्य से एक बड़े सुधार की घोषणा की। सरकार का मानना है कि इस कदम से घर बना रहे मध्यमवर्गीय परिवारों को सीधी राहत पहुंचेगी। मंत्री ने बल्क सीमेंट टर्मिनल पॉलिसी और कंटेनर रेट रेशनलाइजेशन कार्यक्रम के बाद बताया कि रेलवे ने बल्क सीमेंट परिवहन के लिए 90 पैसे प्रति जीटीकेएम की एकसमान दर लागू की है। जीटीकेएम का अर्थ है सकल टन-किलोमीटर। यह रेलवे और माल ढुलाई उद्योग में परिवहन शुल्क की गणना के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक मानक उपाय है। 1 जीटीकेएम, 1 किलोमीटर के लिए 1 सकल टन भार परिवहन के बराबर है। जब रेलवे 90 पैसे प्रति जीटीकेएम दर बताता है, तो इसका मतलब है कि एक किलोमीटर से यात्रा दूरी पर परिवहन किए गए प्रत्येक सकल टन सीमेंट के लिए शुल्क 0.90 रुपये है। इससे माल ढुलाई शुल्क को मानकीकृत करने और लागत की गणना को सरल और अधिक पारदर्शी बनाने में मदद मिलती है। इस समस्या के समाधान के लिए रेलवे ने विशेष रूप से भारी मात्रा में सीमेंट की ढुलाई के लिए डिजाइन किया गया एक विशेष टैंक कंटेनर विकसित किया है। वैष्णव ने कहा कि इस टैंक कंटेनर को सीमेंट फैक्ट्री में भरा जा सकता है। भरने के बाद, इसे देश भर में जहां भी खपत की आवश्यकता हो, वहां ले जाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस प्रणाली से सीमेंट आपूर्ति शृंखला में शामिल लॉजिस्टिक्स लागत में काफी कमी आएगी। वैष्णव ने बताया कि एक समान दर से सीमेंट निर्माताओं को सीमेंट संयंत्रों के स्थान, परिवहन मार्गों और अनलोडिंग टर्मिनलों के बारे में अधिक स्पष्टता मिलेगी। इससे बेहतर योजना बनाने, सीमेंट की बेहतर आवाजाही और उपभोक्ताओं के लिए कम लागत की उम्मीद है। मंत्री ने कहा कि नई टैंक कंटेनर प्रणाली और एक समान दर संरचना भारत भर में सीमेंट परिवहन को युक्तिसंगत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो उद्योग और उपभोक्ताओं दोनों को समर्थन प्रदान करेगी।

टीआईए पोर्टल से निर्यातकों-एमएसएमई को मिलेगा रियल टाइम डाटा सपोर्ट, बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल

नई दिल्ली। व्यापार खुफिया व विश्लेषण (टीआईए) पोर्टल देश के आयातकों, निर्यातकों, स्टार्टअप्स और एमएसएमई के लिए नई जानकारियां उपलब्ध कराएगा। वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने पोर्टल के शुभारंभ के दौरान यह बात कही। वाणिज्य विभाग ने इस पोर्टल को विकसित किया है। टीआईए पोर्टल एक वन-स्टॉप व्यापार खुफिया और विश्लेषण मंच है। पोर्टल में मैक्रो-इकोनॉमिक संकेतकों को जोड़कर 270 से अधिक विश्लेषणात्मक टूल उपलब्ध कराए गए हैं। टीआईए पोर्टल भारत और वैश्विक व्यापार, कमोडिटी व सेक्टोरल रुझानों पर रीयल-टाइम और इंटरएक्टिव इनसाइट्स देता है। इसके जरिए बाजार की स्थिति, निर्यात के अवसर, प्रतिस्पर्धी देशों का विश्लेषण और अन्य व्यापारिक जानकारियां तुरंत देखी जा सकती हैं। इस प्लेटफॉर्म से नीति निर्माताओं, उद्योग और निर्यातकों को अधिक सटीक व त्वरित निर्णय लेने में मदद मिलने की उम्मीद है। इसमें पीएलआई (उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन) और महत्वपूर्ण खनिजों से संबंधित विनिर्माण क्षेत्रों के लिए स्वचालित व्यापार रिपोर्ट और व्यापार प्रवृत्तियों पर नजर रखना भी शामिल है। विभाग के आर्थिक सलाहकार वनलालरम सांगा ने कहा कि पोर्टल को हितधारकों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। उनके इनपुट के आधार पर इसे आगे बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही यह पोर्टल भारत के द्विपक्षीय व्यापार गतिशीलता के साथ-साथ 220 से अधिक देशों के बीच वैश्विक व्यापार प्रवाह को समझने में गहराई और व्यापकता प्रदान करता है। पोर्टल का ट्रेड वॉच टावर फीचर देशों और कमोडिटी स्तर पर गहन व्यापार विश्लेषण उपलब्ध कराएगा। इसमें विशेष टूल और विजुअलाइजेशन शामिल हैं, जिनकी मदद से उपयोगकर्ता वैश्विक और द्विपक्षीय व्यापार रुझानों को आसानी से पहचान सकेंगे।

कमजोर शुरुआत के साथ खुला शेयर बाजार; सेंसेक्स में सीमित हलचल, निफ्टी 25900 से नीचे

नई दिल्ली। वैश्विक बाजारों के कमजोर रुख और विदेशी पूंजी की ताजा निकासी के चलते बुधवार को शुरुआती कारोबार में प्रमुख शेयर सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट दर्ज की गई। शुरुआती कारोबार में 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 135.8 अंक गिरकर 84,537.22 पर आ गया। 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 53.85 अंक गिरकर 25,856.20 पर आ गया। शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 9 पैसे बढ़कर 88.51 के स्तर पर पहुंच गया। सेंसेक्स की कंपनियों में टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स, एचडीएफसी बैंक, बजाज फिनसर्व, एनटीपीसी और सन फार्मा पिछड़ने वाले शेयरों में शामिल रहे। वहीं, इन्फोसिस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा और आईसीआईसीआई बैंक लाभ में रहे।

एशियाई बाजारों में दिखी गिरावट

एशियाई बाजारों में, दक्षिण कोरिया का कोस्पी, शंघाई का एसएसई कम्पोजिट सूचकांक और हांगकांग का हैंग सेंग सूचकांक नीचे कारोबार कर रहा था, जबकि जापान का निक्केई 225 सूचकांक ऊपर कारोबार कर रहा था। मंगलवार को अमेरिकी बाजार नकारात्मक दायरे में बंद हुए।

वैश्विक बाजार दबाव में कर रहे कारोबार

ऑनलाइन ट्रेडिंग और वेल्थ टेक फर्म एनरिच मनी के सीईओ पोनमुडी आर ने कहा कि वैश्विक शेयर बाजार दबाव में कारोबार कर रहे हैं, जिससे अस्थिरता का दौर जारी है और एसएंडपी 500 और नैस्डैक जैसे प्रमुख अमेरिकी सूचकांक महीनों की सबसे लंबी गिरावट की ओर बढ़ रहे हैं। यह कमजोरी कोई घबराहट से प्रेरित गिरावट नहीं है, बल्कि 2025 के अधिकांश समय में अत्यधिक तेजी के बाद एक व्यापक और स्वस्थ सुधार है।

फेडरल रिजर्व के रुख का पड़ा असर

उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी गिरावट एआई और मेगा-कैप टेक्नोलॉजी शेयरों में उत्साह में कमी के कारण आई है। दबाव को बढ़ाते हुए, हाल के दिनों में फेडरल रिजर्व का रुख और अधिक आक्रामक हो गया है।

ब्रेंट क्रूड का भाव गिरकर 64.73 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंचा

वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड का भाव 0.25 प्रतिशत गिरकर 64.73 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया। एक्सचेंज के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने मंगलवार को 728.82 करोड़ रुपये के शेयर बेचे। हालांकि, घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने 6,156.83 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे। मंगलवार को सेंसेक्स 277.93 अंक या 0.33 प्रतिशत गिरकर 84,673.02 पर बंद हुआ। निफ्टी 103.40 अंक या 0.40 प्रतिशत गिरकर 25,910.05 पर बंद हुआ।

चांदी में आएगा जबरदस्त उछाल, इस लेवल तक जाएंगी कीमतें

बिजनेस डेस्क। चांदी इस समय कीमती धातुओं में सबसे आकर्षक ट्रेडिंग ऑप्शन बन गई है। Emkay Wealth Management की ताजा रिपोर्ट के अनुसार आने वाले महीनों में चांदी की कीमतों में तेज उछाल मिल सकता है। फिलहाल चांदी की कीमत करीब 48.80 प्रति औंस है। हाल की गिरावट प्रॉफिट बुकिंग और अमेरिका-चीन के बीच मिनरल से जुड़े नियमों में ढील के कारण दिखी थी। रिपोर्ट का अनुमान है कि चांदी की कीमतें पहले 52-53 प्रति औंस, फिर 58 और आगे चलकर 62 प्रति औंस तक जा सकती हैं। चांदी के लिए 47.60 का स्तर मजबूत सपोर्ट माना जा रहा है, जबकि इसके टूटने पर 45.60 और 42.00 जैसे निचले स्तरों पर भी सहारा मिल सकता है। रिपोर्ट चेतावनी देती है कि चांदी की कीमतें काफी वोलाटाइल रहती हैं, इसलिए निवेशकों को 6-12 महीने की रणनीति और तय टार्गेट के साथ निवेश करना चाहिए। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि पिछले एक साल में Silver ETF और Silver FoF, दोनों ने ही फिजिकल सिल्वर के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया है। 31 अक्टूबर 2025 तक ICICI Prudential Silver ETF और Nippon India Silver ETF ने एक साल में 50फीसदी से अधिक रिटर्न दिया, जबकि इसी अवधि में फिजिकल सिल्वर में लगभग 49फीसदी की बढ़त दर्ज हुई। पिछले तीन और छह महीनों में भी इन फंड्स का प्रदर्शन 34फीसदी से 56फीसदी के बीच रहा। AUM के लिहाज से Nippon India Silver ETF 15,284 करोड़ रुपए के साथ सबसे बड़ा फंड है, जबकि ICICI Prudential Silver ETF 9,481 करोड़ रुपए के साथ दूसरे स्थान पर है। स्ढ्ढ1द्ध स्नस्नड्ढ का रिटर्न भी करीब 49-50फीसदी रहा, हालांकि फंड के खर्चों के कारण श्वञ्जस्न की तुलना में उनका प्रदर्शन थोड़ा कम रहा। निवेशकों को सलाह दी गई है कि वे फिजिकल सिल्वर की जगह Silver ETF या Silver FoF में निवेश करें, क्योंकि ये विकल्प ज्यादा आसान, सुरक्षित और लिक्विडिटी वाले हैं। Emkay का सुझाव है कि निवेशक 6-12 महीने की अवधि को ध्यान में रखते हुए निवेश करें और 52-53, फिर 58 और आगे चलकर 62 के स्तर पर पहुंचने पर मुनाफा बुक कर लें। चांदी को मुख्य निवेश की तरह नहीं बल्कि सपोर्ट देने वाले सैटेलाइट निवेश के रूप में रखने की सलाह दी गई है, क्योंकि इसकी कीमतें सोने की तुलना में अधिक उतार-चढ़ाव दिखाती हैं। साथ ही निवेशकों को फेडरल रिजर्व की नीतियों और वैश्विक राजनीतिक परिदृश्यों पर भी नजर बनाए रखना चाहिए, क्योंकि इनका चांदी की कीमतों पर सीधा असर पड़ता है।

कभी भी फट सकता है एआई बबल! गूगल सीईओ की बड़ी चेतावनी

बिजनेस डेस्क। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर बड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि एआई पर अंधा भरोसा करना गलत है, क्योंकि यह तकनीक अभी भी गलतियां कर रही है। पिचाई के मुताबिक, मौजूदा समय में एआई में हो रहा भारी निवेश एक तरह के बबल जैसा है, जो कभी भी फट सकता है और इसका असर दुनिया की लगभग हर कंपनी पर पड़ेगा, जिसमें गूगल भी शामिल है। पिचाई ने कहा कि एआई का इस्तेमाल केवल एक वैकल्पिक सूचना स्रोत की तरह करना चाहिए, न कि पूरी तरह से उस पर निर्भर होना चाहिए। उन्होंने साफ कहा कि आज भी लोग भरोसेमंद जानकारी के लिए गूगल सर्च का ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कंपनी के पास ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो ज्यादा सटीक और विश्वसनीय जानकारी देने में सक्षम हैं। इसके मुकाबले एआई टूल्स अभी भी कई बार गलत जवाब देते हैं, इसलिए इनके आउटपुट को आंख बंद करके सही नहीं मान लेना चाहिए। पिचाई ने आगे कहा कि एआई क्रिएटिव कामों में बहुत उपयोगी साबित हो सकता है लेकिन इसकी सीमाओं को समझना जरूरी है।

उन्होंने सलाह दी कि यूजर्स को एआई टूल्स का इस्तेमाल समझदारी के साथ करना चाहिए और यह जानना होगा कि कौन-सी स्थिति में एआई पर कितना भरोसा किया जा सकता है। गूगल की एआई रणनीति के बारे में बात करते हुए पिचाई ने बताया कि कंपनी की मजबूती इस बात में है कि उसकी ज्यादातर टेक्नोलॉजी चिप्स, डेटा, एआई मॉडल और रिसर्च गूगल खुद विकसित करता है। इससे कंपनी को एआई मार्केट में आने वाली चुनौतियों का सामना करने में बढ़त मिलती है। इसके साथ ही गूगल ब्रिटेन में अपनी उपस्थिति और मजबूत करने की दिशा में बढ़ रहा है। कंपनी अगले दो साल में यूके में रिसर्च और इंफ्रास्ट्रक्चर पर 5 अरब पाउंड के बड़े निवेश की तैयारी कर रही है। पिचाई के अनुसार, गूगल ब्रिटेन में बड़े पैमाने पर निवेश करने के लिए पूरी तरह तैयार है और वहां अपने एआई इकोसिस्टम का विस्तार करना चाहता है।

टाटा कैपिटल को जेपी मॉर्गन की ओवरवेट रेटिंग, शेयर में जबरदस्त तेजी के संकेत

बिजनेस डेस्क।

ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म जेपी मॉर्गन ने टाटा ग्रुप की नई लिस्टेड कंपनी टाटा कैपिटल लिमिटेड पर अपनी रिपोर्ट जारी की है। ब्रोकरेज ने स्टॉक पर 'ओवरवेट' रेटिंग दी है और 370 का टारगेट प्राइस निर्धारित किया है। यह मंगलवार के बंद भाव से करीब 15 फीसदीकी संभावित तेजी का संकेत देता है। जेपी मॉर्गन का कहना है कि टाटा कैपिटल अपनी बेहतर लायबिलिटी प्रोफाइल, विविध प्रोडक्ट पोर्टफोलियो और मजबूत ओमनी-चैनल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की बदौलत आने वाले वर्षों में तेजी से ग्रोथ कर सकती है। ब्रोकरेज के अनुसार कंपनी मार्केट शेयर बढ़ाने की दिशा में अच्छी स्थिति में है। रिपोर्ट के अनुसार टाटा कैपिटल की रिस्क बिकोर ग्रोथ रणनीति उसे इंडस्ट्री में अलग पहचान देती है। इसी कारण कंपनी का ग्रॉस NPA और क्रेडिट कॉस्ट इंडस्ट्री में सबसे कम है। मजबूत रिस्क मैनेजमेंट कंपनी को किसी भी एसेट क्वालिटी दबाव के दौरान बेहतर स्थिति में रखता है। जेपी मॉर्गन ने अनुमान लगाया है कि टाटा मोटर्स फाइनेंस के विलय के चलते FY26 में ROA लगभग 1.9फीसदी तक सीमित रह सकता है। हालांकि NIMs, क्रेडिट कॉस्ट और ऑपरेटिंग कॉस्ट में सुधार की गुंजाइश बनी हुई है। ब्रोकरेज का अनुमान है कि FY26 से FY28 के बीच टाटा कैपिटल का नेट प्रॉफिट लगभग 30फीसदी CAGR से बढ़ सकता है। साथ ही ROE 13.5फीसदी से 14.5फीसदी के बीच रह सकता है। टाटा कैपिटल का शेयर वर्तमान में FY27 की अनुमानित बुक वैल्यू के 2.6x कऊपर ट्रेड कर रहा है। जेपी मॉर्गन इसे आकर्षक वैल्यूएशन और बेहतर रिस्क-रिवॉर्ड प्रोफाइल मानता है। इससे पहले दो अन्य ब्रोकरेज फर्म भी इस स्टॉक को ADD' रेटिंग दे चुकी हैं।

कच्चे तेल में नरमी से रुपए को मिला सहारा, डॉलर के मुकाबले आज इतना हुआ मजबूत

मुंबई। रुपया बुधवार को शुरुआती कारोबार में नौ पैसे की बढ़त के साथ 88.51 प्रति डॉलर पर पहुंच गया। कच्चे तेल की कीमतों में नरमी से रुपए को समर्थन मिला हालांकि वैश्विक स्तर पर शेयर बाजारों में उतार-चढ़ाव के कारण निवेशकों की धारणा प्रभावित हुई। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 88.57 प्रति डॉलर पर खुला। शुरुआती सौदों के बाद डॉलर के मुकाबले 88.51 पर पहुंच गया जो पिछले बंद भाव से नौ पैसे की बढ़त दर्शाता है। रुपया मंगलवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 88.60 पर बंद हुआ था। इस बीच, छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.04 प्रतिशत की बढ़त के साथ 99.49 पर आ गया। घरेलू शेयर बाजारों में सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 46.27 अंक या 0.05 प्रतिशत की गिरावट के साथ 84,626.75 अंक पर और निफ्टी 8.35 अंक या 0.03 प्रतिशत फिसलकर 25,901.70 अंक पर आ गया। अंतरराष्ट्रीय मानक ब्रेंट क्रूड 0.34 प्रतिशत की गिरावट के साथ 64.67 डॉलर प्रति बैरल के भाव पर रहा। शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) मंगलवार को बिकवाल रहे थे और उन्होंने शुद्ध रूप से 728.82 करोड़ रुपये के शेयर बेचे।

रोहित शर्मा से छिन गई नंबर-1 की कुर्सी, ये बल्लेबाज बना वनडे क्रिकेट का नया बादशाह, रचा इतिहास

नई दिल्ली। दिग्गज भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा अब वनडे क्रिकेट में नंबर-1 बल्लेबाज नहीं हैं. न्यूजीलैंड के डेरिल मिचेल ने हिटमैन से ये कुर्सी छीन ली है. दूसरे की ओर से जारी की गई ताजा रैंकिंग में डेरिल मिचेल ने रोहित शर्मा को पीछे छोड़ दिया और वनडे फॉर्मेट में दुनिया के नए नंबर-1 बल्लेबाज बन गए. डेरिल मिचेल को वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में शानदार बल्लेबाजी के लिए यह इनाम मिला. वनडे में मिचेल पहली बार नंबर-1 बल्लेबाज बने हैं. इसके साथ ही इस कीवी क्रिकेटर ने इतिहास भी रच दिया. ऑस्ट्रेलिया दौरे पर वनडे सीरीज में धमाकेदार बल्लेबाजी के बाद रोहित शर्मा को हुए थे इस फॉर्मेट का नंबर-1 बल्लेबाज घोषित किया था. भले ही भारत 3 मैचों की वनडे सीरीज 2-1 से हार गया था, लेकिन रोहित ने अपनी बल्लेबाजी से सबका दिल जीत लिया था. दूसरे वनडे में अर्धशतक और फिर सिडनी में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए शतक जड़ा था. इस प्रदर्शन का ही इनाम उन्हें वनडे के नंबर-1 बल्लेबाज के रूप में मिला. हालांकि, अब डेरिल मिचेल ने इस कुर्सी पर कब्जा जमा लिया है.

डेरिल मिचेल ने किया कमाल

डेरिल मिचेल ने वनडे बल्लेबाजों की रैंकिंग में दो पायदान की छलांग लगाई, जिससे वह सीधे टॉप पर पहुंच गए. उनके 782 रेटिंग अंक है. वहीं, रोहित शर्मा 781 रेटिंग अंक लेकर दूसरे स्थान पर मौजूद है. तीसरे स्थान पर अफगानिस्तान के इब्राहिम जादरान का नाम है. डेरिल मिचेल को वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में शानदार प्रदर्शन का फायदा मिला. उन्होंने ओपनिंग मैच में 119 रन की बेहतरीन पारी खेलकर न्यूजीलैंड को 7 रन से जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई.

नंबर-1 बनते ही रचा इतिहास

डेरिल मिचेल न्यूजीलैंड के लिए वनडे में नंबर-1 बल्लेबाज की रैंकिंग हासिल करने वाले सिर्फ दूसरे बल्लेबाज ही है. इससे पहले 1979 में किसी कीवी बल्लेबाज ने यह करिश्मा किया था. न्यूजीलैंड के महान बल्लेबाज ग्लेन टर्नर ने उस समय वनडे बल्लेबाजों की रैंकिंग में नंबर-1 का स्थान कब्जाया था. मार्टिन क्रो, एंड्रयू जोन्स, रोजर ट्वोस, नाथन एस्टल, केन विलियमसन, मार्टिन गुप्टिल और रॉस टेलर जैसे न्यूजीलैंड के दिग्गज अपने शानदार करियर के दौरान वनडे बल्लेबाजों की रैंकिंग में टॉप-5 में जरूर पहुंचे, लेकिन नंबर-1 नहीं बन पाए. अब 46 साल बाद किसी कीवी क्रिकेटर ने ये उपलब्धि हासिल कर इतिहास रच दिया.

तय नजर आ रही थी हार, आखिरी 12 गेंदों पर पलटा मैच, न्यूजीलैंड ने जीती वेस्टइंडीज से सीरीज

नेपियर। न्यूजीलैंड ने दूसरे वनडे में वेस्टइंडीज पर पांच विकेट से रोमांचक जीत दर्ज की. अब न्यूजीलैंड के पास तीन मैच की वनडे सीरीज में 2-0 की अजेय लीड है. श्रृंखला का आखिरी मैच 22 नवंबर को हैमिल्टन में खेला जाएगा. जो कैरेबियन टीम के लिए प्रतिष्ठा का सवाल होगा. दूसरे मैच की बात करें तो बारिश के चलते यह मुकाबला 34-34 ओवर का कर दिया गया था. 248 रन के लक्ष्य का पीछा करते उतरी मेजबान कीवी टीम एक वक्त 194 रन पर पांच विकेट गंवा चुकी थी. विकेटों के पतझड़ के बीच हार तय नजर आ रही थी. सात ओवर में 74 रन तो आखिरी दो ओवर में 22 रन की दरकार थी. लेकिन कप्तान मिचेल सेंटनर (15 गेंद में नाबाद 34) और टॉम लाथम (29 गेंद में नाबाद 39) ने अपनी नब्ज पर काबू रखते हुए मैच निकाल लिया.

शाई होप का ऐतिहासिक शतक बेकार

इससे पहले वेस्टइंडीज ने टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी करते हुए शाई होप के कमाली शतक के बूते नौ विकेट खोकर 247 रन बनाए थे. होप के बल्ले से 69 गेंद में रन की ऐतिहासिक पारी निकली थी. इसके साथ ही वह सभी फुल मेंबर (11 टीम) के खिलाफ सेंचुरी जमाने वाले दुनिया के एकमात्र बल्लेबाज भी बन चुके है.

कॉन्वे ने खेली 90 रन की पारी

न्यूजीलैंड के कप्तान सेंटनर जब मैदान पर उतरे तो न्यूजीलैंड को 29 गेंद पर 54 रन की जरूरत थी, लेकिन उन्होंने 15 गेंदों पर 34 रन बनाकर उस तरह की शानदार पारी खेली, जिसकी वेस्टइंडीज अब इस दौर पर आदी हो गई है. दूसरे छोर पर लाथम मौजूद थे, जिन्होंने अपने कप्तान का बखूबी साथ निभाया. इससे पहले डेवोन कॉनवे और रचिन रवींद्र ने लय तय कर दी थी. रवींद्र अपना अर्धशतक पूरा करने के बाद आउट हो गए, लेकिन कॉनवे ने अहम भूमिका निभाई, उनके बल्ले से 90 रन निकले.

8 गेंदबाज भी नहीं रोक पाए... राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाज ने ठोकी तूफानी सेंचुरी, भारतीय बॉलर्स को किया बेदम

नई दिल्ली। लुहान-ड्रे प्रिटोरियस ने भारतीय गेंदबाजों की जमकर धुनाई करते हुए शानदार शतक जड़ा. प्रिटोरियस इस समय भारत दौरे पर है जहां दक्षिण अफ्रीका ए टीम इंडिया ए के साथ 3 मैचों की वनडे सीरीज खेल रही है. सीरीज के तीसरे और आखिरी वनडे में प्रिटोरियस ने 123 रन की दमदार पारी खेली. कप्तान तिलक वर्मा ने अपने आठ गेंदबाजों को आजमाया लेकिन इनमें से कोई भी गेंदबाज प्रिटोरियस को शतक जड़ने से नहीं रोक सका. बाएं हाथ के बल्लेबाज प्रिटोरियस ने राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम के चारों ओर शॉट लगाए. राजस्थान रॉयल्स ने प्रिटोरियस को आईपीएल 2026 के अगामी सीजन के लिए रिटेन किया है.प्रिटोरियस ने 87 गेंदों पर शतक जड़ा जबकि 98 गेंदों पर 125.51 की स्ट्राइक रेट से 123 रनों की शानदार पारी खेली. 19 साल के बाएं हाथ के बल्लेबाज लुहान-ड्रे प्रिटोरियस की शानदार पारी के दम पर दक्षिण अफ्रीका ए ने 50 ओवर में 6 विकेट पर 325 रन बनाए. प्रिटोरियस ने अपनी शतकीय पारी में नौ चौके और छह छक्के लगाए. उन्होंने साथी शतकवीर रिवाल्डो मूनसामी (130 गेंदों पर 107 रन) के साथ पहले विकेट के लिए 241 रनों की साझेदारी की. यह प्रिटोरियस का लिस्ट ए क्रिकेट में सर्वोच्च स्कोर और तीसरा शतक है. उन्होंने अब लिस्ट ए क्रिकेट में 47.94 की औसत और 109 के स्ट्राइक रेट से 863 रन बनाए है.

इंडिया ए की ओर से खलील अहमद, प्रसिद्ध कृष्णा और हर्षित राणा जैसे वर्ल्ड क्लास गेंदबाज बॉलिंग कर रहे थे राजस्थान रॉयल्स ने प्रिटोरियस को आईपीएल 2026 के लिए रिटेन किया है. भारतीय तेज गेंदबाज खलील अहमद की गेंद पर चौका लगाकर खाता खोलने के बाद लुआन-ड्रे प्रीटोरियस ने लय पकड़ ली. उन्होंने नियमित अंतराल पर बाउंड्री लगाई जिसके बाद भारतीय गेंदबाज उनके सामने बेदम नजर आए. प्रिटोरियस ने 13वें ओवर में मिडविकेट पर एक शानदार स्लॉग स्वीप लगाकर मात्र 39 गेंदों पर अर्धशतक पूरा किया .और तीन ओवर बाद अपनी टीम के स्कोर को 100 रन के पार पहुंचा दिया. प्रटोरियस ने 33वें ओवर में अपना शतक पूरा किया और प्रोटियाज ने 200 का आंकड़ा पार कर लिया.

बदोनी की गेंद पर लगातार तीन छक्के जड़े

प्रिटोरियस ने दो ओवर बाद और भी आक्रामक रुख अपनाया. उन्होंने आयुष बदोनी की लगातार तीन गेंदों पर छक्के जड़े और आखिरकार 38वें ओवर में साथी सलामी बल्लेबाज मूनसामी के आउट होने के कुछ ही देर बाद वह भी पवेलियन लौट गए. प्रिटोरियस की यह पारी 2025 में दक्षिण अफ्रीका के लिए उनकी बढ़ती प्रतिष्ठा में चार चांद लगा दी. इस बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए एक शानदार साल रहा है.

लुआन-ड्रे प्रिटोरियस के लिए शानदार रहा यह साल

साल की शुरुआत में लुआन-ड्रे प्रिटोरियस जून में अपने डेब्यू टेस्ट में शतक बनाने वाले सबसे कम उम्र के दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी बनकर अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी पहचान बनाई. 19 साल और 93 दिन की उम्र में 113 गेंदों में अपना टेस्ट पहला शतक पूरा करने वाले प्रटोरियस ने बुलावायो में जिम्बाब्वे के खिलाफ 160 गेंदों पर 153 रनों की पारी खेली. प्रटोरियस टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में डेब्यू मैच में 150 रन बनाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी भी बने.उन्होंने पाकिस्तान के जावेद मियांदाद का रिकॉर्ड तोड़ा था जिन्होंने 1976 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 163 रन 19 साल और 119 दिन की उम्र में यह उपलब्धि हासिल की थी. इस युवा बल्लेबाज ने अपने पहले ही वनडे मैच में अर्धशतक भी लगाया. इस महीने की शुरुआत में पाकिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज के पहले मैच में उन्होंने 60 गेंदों में 57 रन बनाए.

दांत पीसकर क्यों गेंदबाजी करते हैं जसप्रीत बुमराह, नेट्स पर केएल राहुल के गिड़गिड़ाने की कहानी, भाई बोलने में भलाई

नई दिल्ली। पूरी दुनिया बुमराह से खौफ खाती है ये तो हर कोई जानता है पर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जस्सी से उनके टीम के साथी खिलाड़ी भी घबराते है. इंडिया के स्टार बल्लेबाज केएल राहुल ने जसप्रीत बुमराह को लेकर एक इंटरव्यू में कहा कि 'नेट प्रैक्टिस के दौरान उन्हें छेड़ना खतरे से खाली नहीं होता. उनका माना कि नेट में बुमराह की गेंदों को खेलते वक्त ज्यादातर बल्लेबाज बहुत सावधानी बरतते हैं क्योंकि उनका ईगो हर्ट करने से बचते है. और वो कोई ऐसा वैसा शॉट खेलने से बचते हैं जिससे बुमराह का ईगो हर्ट हो जाए. दरअसल, ये सब बात केएल राहुल के दिए गए इंटरव्यू में हुई और इस दौरान उनसे पूछा कि 'नेट में अगर कोई बुमराह की गेंद पर कराय शॉट लगा देता है तो क्या बुमराह को गुस्सा आता है? इसके जवाब में केएल राहुल ने कहा, 'बहुत, बहुत नाराज हो जाता है. लेकिन सबसे पहले तो ये बता दूं कि नेट में उसे शॉट लगाना आसान नहीं होता. और बहुत कम लोग ही ऐसा कर पाते है. केएल राहुल ने बताया कि 'बुमराह जैसे मैचों में गेंदबाजी करते है , उसी शिद्दत से नेट में भी बॉलिंग करते है और 'वो तो दांत पीसता ही रहता है. हर समय जब आप उसका चेहरा देखेंगे तो जैसे मुकाबले के लिए तैयार रहता है.कभी-कभी हमें कहना पड़ता है, यार बुमराह हम एक ही टीम में हैं. ठीक है नेट्स में मिलने वाले विकेट की गिनती नहीं होती, तब वो हंसता है. मैं अक्सर ये कहकर उसे शांत कराता हूं कि भाई, आपको खेलना नामुमकिन है आप बहुत अच्छे है, गेंद थोड़ा धीमा फेंको यार. नेट्स पर बुमराह उन गिने चुने गेंदबाजों में से एक है जो नो बॉल करने से परहेज करते है.

नेट्स पर रहता है खतरा

बुमराह को सबसे खतरनाक गेंदबाज करार देते हुए केएल राहुल ने कहा, 'निश्चित तौर पर वो ऐसे गेंदबाज हैं जिनको हिट करना सबसे मुश्किल है. मैं सोचता हूं कि हम तो उसे हमेशा खेलते है, उसके ऐक्शन और वह कब कैसे गेंद रिलीज करता है, उससे लगभग परिचित है लेकिन विपक्षी टीम के बल्लेबाज के लिए, दूसरे देश के बल्लेबाज के लिए उन्हें खेलना बहुत मुश्किल है. वो तो पहले उनके खिलाफ विकेट बचाएगा उसके बाद रन बनाने के बारे में सोचेगा सच में उन्हें खेलना बहुत मुश्किल है. बुमराह उन गेंदबाजों में से एक है जिनको पिच के बारे में ज्यादा सोचना नहीं पड़ता. कोलकाता की रैंक टर्नर पर पहली पारी में 5 विकेट लेना अपने आप में सबसे बड़ा उदाहरण है.

क्या गंभीर को टेस्ट में कोच पद से हटा देना चाहिए? गांगुली ने दिया चौंकाने वाला जवाब

कोलकाता। भारत और दक्षिण अफ्रीका पहले टेस्ट में मिली 30 रन की हार के बाद ईडन गार्डन्स की पिच को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। भारतीय टीम एक बल्लेबाज कम लेकर उतरी और उसी पिच पर पहले ही दिन से तेज उछाल और अनियमित टर्न दिखना शुरू हो गया। इसी बीच सोशल मीडिया पर फैंस ने मुख्य कोच गौतम गंभीर और टीम मैनेजमेंट की रणनीति पर सवाल खड़े किए। साथ ही गंभीर को टेस्ट कोच के पद से हटा देने की भी मांग उठी। अब इस मामले पर पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष और कैब प्रमुख सौरव गांगुली की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने गंभीर को हटाने की मांग पर जवाब दिया है। गांगुली ने कहा, गौतम गंभीर को हटाने का कोई सवाल ही नहीं है। इंग्लैंड में उन्होंने और शुभमन गिल ने बेहतरीन काम किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि वे भारत में भी शानदार प्रदर्शन करेंगे। सबसे बड़ी चर्चा इस बात पर रही कि आखिर ईडन गार्डन्स की पिच ऐसी क्यों तैयार हुई? क्या गांगुली से कोई सलाह ली गई थी? इस सवाल पर उन्होंने इंडिया टुडे से बात करते हुए दो-टूक जवाब देते हुए कहा, नहीं, मैं इसमें बिल्कुल शामिल नहीं होता। बीसीसीआई के क्यूरेटर टेस्ट मैच से चार दिन पहले विकेट का पूरा काम संभाल लेते हैं। हमारी अपनी क्यूरेटर टीम भी है, लेकिन अनुरोध भारतीय टीम प्रबंधन की ओर से आते हैं और उन्हीं के अनुरोध के अनुसार पिच बनाई जाती है। गांगुली ने यह भी माना कि यह पिच भारतीय बल्लेबाजों के लिए उपयुक्त नहीं थी। उन्होंने कहा, पिच बिल्कुल अच्छी नहीं थी। टॉप-ऑर्डर और मिडिल-ऑर्डर बल्लेबाज इससे बेहतर विकेट डिजर्व करते हैं। ईडन में तीन दिनों तक पूरा स्टेडियम भरा रहा, ऐसे में टीम को अच्छी सतह पर खेलना चाहिए था। ईडन गार्डन्स के क्यूरेटर सुजान मुखर्जी ने भी स्पष्ट किया कि पिच टीम प्रबंधन की मांग पर ही तैयार की गई थी। उन्होंने कहा, हम हमेशा टीम और कोच की मांग के अनुसार पिच तैयार करते हैं। और इसी अनुरोध के अनुसार वही पिच बनाई गई थी जो कोच गौतम गंभीर चाहते थे।

सुंदर के रोल को लेकर तकरार तेज : क्या गलत फैसले की कीमत चुका रही टीम इंडिया? गांगुली-कार्तिक ने उठाए गंभीर सवाल

नई दिल्ली । भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच कोलकाता में खेले गए पहले टेस्ट की हार ने न सिर्फ टीम की बल्लेबाजी पर सवाल उठाए, बल्कि मुख्य कोच गौतम गंभीर के फैसलों को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। सबसे बड़ी बहस वॉशिंगटन सुंदर को नंबर तीन पर भेजने को लेकर छिड़ गई है। एक ऐसा फैसला जिसने पूर्व कप्तान सौरव गांगुली और पूर्व विकेटकीपर दिनेश कार्तिक दोनों को हैरान कर दिया।

नंबर-3 पर सुंदर का प्रमोशन-कार्तिक का कड़ा सवाल

दिनेश कार्तिक ने वॉशिंगटन सुंदर को नंबर-तीन भेजने को लेकर पर सीधा सवाल दागा कि इससे उनके गेंदबाजी कौशल को नुकसान होगा। कार्तिक ने क्रिकबज से कहा, अगर आप उन्हें नंबर तीन भेज रहे हैं, तो आप उनसे कह रहे हैं कि अब बल्लेबाजी पर ज्यादा फोकस करो। लंबे समय तक बैटिंग प्रैक्टिस करेगा तो गेंदबाजी की तैयारी कम हो जाएगी। दोनों में एक साथ बेस्ट बने रहना लगभग नामुमकिन है। सुंदर ने 29 और 31 रन बनाकर टीम में महत्वपूर्ण योगदान जरूर दिया था, लेकिन कार्तिक के मुताबिक यह प्रमोशन सिर्फ एक अस्थायी समाधान जैसा दिखता है। कार्तिक ने साफ कहा, यह बहुत ट्रिकी स्थिति है। नंबर-तीन उसकी लंबे समय की भूमिका नहीं लगती। इससे उसकी गेंदबाजी भविष्य में प्रभावित हो सकती है।

गांगुली भी सहमत-सुंदर नंबर-तीन के लिए नहीं बने

सौरव गांगुली ने भी इस बात को दृढ़ता से उठाया कि वॉशिंगटन सुंदर टेस्ट क्रिकेट में नंबर-तीन की भूमिका के लिए तैयार नहीं है, खासकर विदेशी परिस्थितियों में। गांगुली ने इंडिया टुडे से कहा, वह अच्छे क्रिकेटर हैं, गेंदबाजी भी करते है, बैटिंग भी करते है, लेकिन मैं नहीं मानता कि नंबर-तीन टेस्ट क्रिकेट में उनके लिए लंबे समय का विकल्प है। उन्होंने स्पष्ट किया कि शीर्ष क्रम में सिर्फ स्पेशलिस्ट बल्लेबाज होने चाहिए। गांगुली ने कहा, आपके पहले पांच बल्लेबाज, ओपनर्स से लेकर नंबर-पांच तक, हर हालात में परफॉर्म करने वाले स्पेशलिस्ट होने चाहिए। मैं आश्वस्त नहीं कि वॉशिंगटन इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका या न्यूजीलैंड में भारत के नंबर-तीन हो सकते हैं।

कोलकाता टेस्ट में गौतम गंभीर की रणनीति पर गांगुली ने और भी बड़े सवाल उठाए। भारत ने चार स्पिनरों के साथ मैच खेला, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर ने सिर्फ एक ओवर फेंका। गांगुली ने कहा, भारत में चार स्पिनरों की जरूरत नहीं होती, खासकर तब जब वॉशिंगटन ने पूरे टेस्ट में सिर्फ एक ओवर डाला। जब विकेट स्पिन कर रहा है और मुख्य स्पिनर 20-30 ओवर डाल सकते है, तो चार स्पिनरों की जरूरत नहीं।

गंभीर का सुंदर प्रेम, नया रोल या बड़ा रिस्क?

गौतम गंभीर वॉशिंगटन सुंदर की प्रतिभा के बड़े प्रशंसक माने जाते है, लेकिन उन्हें नंबर-तीन भेजना एक बड़े प्रयोग जैसा लग रहा है, जो फिलहाल टीम के लिए लाभ से ज्यादा जोखिम जैसा दिख रहा है। अभी तक सुंदर की मौजूदा भूमिका स्पष्ट नहीं है।

क्या वह मुख्य रूप से बल्लेबाज है या क्या वह गेंदबाजी ऑलराउंडर है या क्या उन्हें गंभीर एक भविष्य के स्पेशलिस्ट बैटर की तरह तैयार कर रहे है? कार्तिक का डर भी यही है। उन्होंने कहा, जिस रोल के लिए सुंदर को बनाया गया है, वह उस दिशा से हट सकते हैं।

पिच विवाद ने बढ़ाया दबाव, गांगुली ने गंभीर को बचाया

पहले टेस्ट की हार के बाद गंभीर की रणनीति पर जब सवाल बढ़े, तो पिच विवाद ने आग में और घी डाल दिया। लेकिन सौरव गांगुली ने साफ कहा कि अभी गंभीर पर कार्रवाई का कोई सवाल नहीं उठता। गांगुली ने कहा, गौतम गंभीर को हटाने का सवाल ही नहीं है। इंग्लैंड में कोच और कप्तान दोनों ने शानदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने पिच को भी कठघरे में रखा और कहा, यह पिच अच्छी नहीं थी। भारतीय टॉप और मिडिल ऑर्डर को इससे बेहतर विकेट मिलना चाहिए था।

सुंदर का नंबर-तीन प्रयोग, बड़ा दांव या गलत दिशा?

पहले टेस्ट की हार के बाद स्पष्ट है कि भारतीय टीम को अपनी बल्लेबाजी संरचना पर गंभीरता से पुनर्विचार करना होगा। सुंदर की प्रतिभा में संदेह नहीं, लेकिन नंबर-तीन एक ऐसा स्थान है जहां टीम को वर्षों तक भरोसेमंद, स्पेशलिस्ट बल्लेबाज चाहिए।

गुवाहाटी टेस्ट से पहले बड़ा सवाल : कप्तान शुभमन गिल खेलेंगे या नहीं? बीसीसीआई ने दिया अपडेट, सुनाई राहत की खबर

मुंबई । भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरे टेस्ट से पहले टीम इंडिया को एक बड़ी राहत और उतनी ही बड़ी चिंता दोनों एक साथ मिली है। कप्तान शुभमन गिल अपनी गर्दन की चोट के बावजूद गुवाहाटी के लिए टीम के साथ रवाना होंगे, लेकिन यह अभी भी साफ नहीं है कि वह मैदान पर उतर पाएंगे या नहीं। बीसीसीआई ने बुधवार को इस बात की आधिकारिक पुष्टि की। कोलकाता टेस्ट के दूसरे दिन शुभमन गिल गंभीर गर्दन दर्द के चलते रिटायर्ड हर्ट हो गए थे और बाद में उन्हें अस्पताल भी ले जाना पड़ा था। भारत वह मुकाबला 30 रन से हार गया और गिल की चोट ने टीम मैनेजमेंट की चिंता और बढ़ा दी। बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने बयान जारी करते हुए कहा, शुभमन को उपचार से काफी राहत मिल रही है और वह 19 नवंबर को टीम के साथ गुवाहाटी रवाना होंगे। उनकी स्थिति पर बीसीसीआई की मेडिकल टीम नजर रखेगी और दूसरे टेस्ट में खेलने को लेकर फैसला बाद में लिया जाएगा। गुवाहाटी में 22 नवंबर से सीरीज का दूसरा टेस्ट शुरू होना है और टीम इंडिया 0-1 से पीछे है। ऐसे में कप्तान गिल का खेलना बेहद अहम होगा, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में उनकी उपलब्धता बेहद संदिग्ध मानी जा रही है। शुभमन गिल के खेलने की संभावना बेहद कम दिख रही है, इसलिए सेलेक्टर्स ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। आंध्र प्रदेश के युवा ऑलराउंडर नीतीश रेड्डी को दक्षिण अफ्रीका ए के खिलाफ भारत ए की चल रही सीरीज से तुरंत हटा दिया गया है और वह कोलकाता पहुंच चुके हैं। बताया जा रहा है कि रेड्डी मंगलवार के नेट सत्र में शामिल नहीं हुए, लेकिन वह टीम के साथ जुड़े रहेंगे ताकि गिल के अंतिम निर्णय के बाद उन्हें प्लेइंग इलेवन में शामिल किया जा सके। रेड्डी न सिर्फ दाएं हाथ के बल्लेबाज है, बल्कि हाल ही में घरेलू क्रिकेट में लगातार अच्छे प्रदर्शन के कारण चयनकर्ताओं की नजर में आए हैं। उनका टेस्ट करियर भले अभी शुरुआत के दौर में है, लेकिन यदि गिल बाहर होते है तो वह गुवाहाटी में खेलते दिख सकते है। गिल की फिटनेस को लेकर सस्पेंस ने टीम इंडिया के बैटिंग कॉम्बिनेशन में बड़ी अनिश्चितता पैदा कर दी है। पहले टेस्ट में शीर्ष क्रम के संघर्ष को देखते हुए गुवाहाटी में गिल की जगह भरना आसान नहीं होगा। ऐसे में देश की निगाहें मेडिकल रिपोर्ट और टीम मैनेजमेंट के अगले फैसले पर टिकी रहेंगी।

बेटे क्रूज के साथ जोड़ी बनाकर टेनिस में वापसी करेंगे लेटिन हेविट; बेल्जियम डेविस कप के सेमीफाइनल में

सिडनी । दो बार के ग्रैंड स्लैम एकल चैंपियन लेटिन हेविट न्यू साउथ वेल्स ओपन एटीपी चैलेंजर प्रतियोगिता में अपने 16 वर्षीय बेटे क्रूज के साथ जोड़ी बनाकर प्रतिस्पर्धी टेनिस में वापसी करेंगे। विश्व के पूर्व नंबर एक खिलाड़ी 44 वर्षीय हेविट ने 2001 में अमेरिकी ओपन और 2002 में विंबलडन जीता था। उन्होंने 2016 में आधिकारिक तौर पर संन्यास ले लिया था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में चुनिंदा टूर्नामेंटों में युगल मुकाबलों में खेलना जारी रखा था। वह वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया की डेविस कप टीम के कप्तान भी हैं। पिता पुत्र की यह जोड़ी पहले दौर में आस्ट्रेलिया के ही हेडन जोन्स और पावेल मारिनकोव का सामना करेंगे। जिजोउ बर्गस ने आर्थर रिंडरनेच को 6-3, 7-6 (4) से पराजित किया जिससे बेल्जियम ने 10 बार के चैंपियन फ्रांस पर 2-0 की जीत के साथ डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह पक्की की। बेल्जियम को फ्रांस के साथ अपने पिछले चार मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा था जिसमें 2017 का फाइनल भी शामिल है। सेमीफाइनल में शुक्रवार को उसका सामना इटली या ऑस्ट्रिया से होगा। अंतिम दो क्वार्टर फाइनल गुरुवार को होंगे जिसमें जर्मनी का सामना अर्जेंटीना से और स्पेन का सामना चेक गणराज्य से होगा। बर्गस ने फ्रांस के शीर्ष खिलाड़ी के खिलाफ शुरू से ही दबदबा बनाए रखा और एक शानदार फोरहैंड विनर के साथ मैच को अपने नाम कर लिया। इससे पहले राफेल कॉलिग्नन ने कोरेंटिन मौटेट को 2-6, 7-5, 7-5 से हराकर बेल्जियम को 1-0 की बढ़त दिलाई थी।

लक्ष्य और प्रणय सहित पांच भारतीय खिलाड़ी ऑस्ट्रेलियाई ओपन के दूसरे दौर में

सिडनी । लक्ष्य सेन और एचएस प्रणय सहित पांच भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार शुरुआत करते हुए बुधवार को यहां 475,000 डॉलर इनामी आस्ट्रेलियाई ओपन सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष एकल के दूसरे दौर में प्रवेश किया। विश्व चैंपियनशिप 2021 के कांस्य पदक विजेता लक्ष्य ने चीनी ताइपे के सु ली यांग को 21-17, 21-13 से हराया, जबकि इस प्रतियोगिता में 2023 के उपविजेता प्रणय ने खराब शुरुआत से उबरते हुए पहले दौर के मैच में दुनिया के 85वें नंबर के खिलाड़ी योहानेस सौत मार्सेलिनो को 57 मिनट में 6-21, 21-12, 21-17 से हराया। लक्ष्य का अगला मुकाबला ची यु जेन या वांग त्जु वेई से होगा जबकि प्रणय इंडोनेशिया के आठवें वरीय अल्वी फरहान से भिड़ेंगे। विश्व के 32वें नंबर के खिलाड़ी और इस वर्ष की शुरुआत में अमेरिकी ओपन में अपना पहला सुपर 300 खिताब जीतने वाले आयुष शेट्टी ने कनाडा के सैम युआन को 33 मिनट में 21-11, 21-15 से पराजित किया। कर्नाटक के इस 20 वर्षीय खिलाड़ी का सामना दूसरे दौर में जापान के चौथे वरीय कोडाई नाराओका से होगा। मकाऊ ओपन के सेमीफाइनलिस्ट थरुण मन्नेपल्ली ने डेनमार्क के मैग्नस योहानसन को 66 मिनट तक चले मुकाबले में 21-13, 17-21, 21-19 से हराया। राष्ट्रीय खेल 2023 के स्वर्ण पदक विजेता मन्नेपल्ली का अगला मुकाबला चीनी ताइपे के पांचवें वरीय लिन चुन-यी से होगा। विश्व चैंपियनशिप 2021 के रजत पदक विजेता अनुभवी किदांबी श्रीकांत भी 64 मिनट तक चले मुकाबले में चीनी ताइपे के लो चिया हाओ को 21-19, 19-21, 21-15 से हराकर अगले दौर में पहुंच गए। इस वर्ष के शुरू में मलेशिया मास्टर्स में उपविजेता रहे श्रीकांत का अगला मुकाबला जापान के शोगो ओगावा या एडवर्ड लाउ से होगा। इस बीच किरण जॉर्ज को कड़ी चुनौती पेश करने के बावजूद जापान के छठी वरीयता प्राप्त केंटा निशिमोतो से 21-11, 22-24, 17-21 से हार का सामना करना पड़ा। निशिमोतो ने पिछले सप्ताह जापान मास्टर्स के सेमीफाइनल में लक्ष्य सेन को हराया था। मोहित जगलान और लक्षिता जगलान की भारतीय मिश्रित युगल जोड़ी को एक अन्य मैच में कनाडा के नाइल याकुरा और क्रिस्टल लाई ने 12-21, 16-21 से हराकर बाहर कर दिया।

कोच थोड़ी जाकर खेल रहा है : पिच विवाद के बीच गंभीर को मिला समर्थन, इस पूर्व क्रिकेटर ने आलोचकों को दिया जवाब

नई दिल्ली । भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेले गए पहले टेस्ट मैच ने क्रिकेट जगत में बड़ी बहस छेड़ दी है। 124 रनों के छोटे से लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय बल्लेबाजों का अचानक ढह जाना और तीन दिन में मैच का खत्म हो जाना कई सवाल छोड़ गया। इसी बीच पिच को लेकर विवाद गहराया, जहां कई विशेषज्ञों ने टीम मैनेजमेंट पर उंगली उठाई। भारत के कोच गौतम गंभीर ने बयान दिया कि टीम को वही विकेट मिला जिसकी उन्होंने मांग की थी और पिच में ऐसा कुछ नहीं था जो 'अनप्लेएबल' कहा जाए। जहां पूर्व स्पिनर हरभजन सिंह ने पिच चयन को लेकर टीम मैनेजमेंट पर सवाल उठाए, वहीं पूर्व क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा ने गंभीर का मजबूती से पक्ष लिया। उथप्पा ने साफ कहा कि हार के लिए कोच को जिम्मेदार ठहराना सरासर गलत है। उन्होंने एक लाइव सेशन में कहा, कोच थोड़ी जा कर खेल रहा है अंदर। उथप्पा ने यह भी कहा कि नतीजों से सीधे कोच को दोष देना उचित नहीं है। उथप्पा ने आलोचकों पर तंज कसते हुए कहा कि जब राहुल द्रविड़ जैसे महान खिलाड़ी को सवालों के घेरे में लाया जा सकता है, तो किसी भी कोच को ट्रोल करना अब आम बात हो गई है। उन्होंने कहा कि इतने हजार अंतरराष्ट्रीय रन बनाना आसान नहीं होता, लेकिन लोग फिर भी द्रविड़ जैसे दिग्गजों पर अंगुलियां उठाते है। उथप्पा ने कहा, हम नतीजों को देख रहे है और कोच को दोष दे रहे है, लेकिन आपको समग्र परिदृश्य को देखना होगा। जब उन्होंने राहुल द्रविड़ की आलोचना की, तो मुझे यह बात समझ नहीं आई। 20-30 हजार अंतरराष्ट्रीय रन बनाना आसान नहीं है। इसलिए, अगर उन्हें ट्रोल किया जा सकता है, तो किसी को भी ट्रोल किया जा सकता है।

घरेलू क्रिकेट में पिचों को लेकर अलग नियम क्यों?

उथप्पा ने एक और अहम मुद्दा उठाया। उन्होंने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय पिचों के बीच दोहरे मानदंड को लेकर सवाल किए। उन्होंने कहा, हमने घरेलू टूर्नामेंट्स में तटस्थ क्यूरेटर बुलाए और नियंत्रित किया कि हम किस तरह के विकेट तैयार करने वाले है। क्योंकि अगर कोई मैच दो दिन में खत्म हो जाता था, तो ग्राउंड्समैन और एसोसिएशन को फटकार लगाई जाती थी। लेकिन यहां तो मैच ढाई दिन में खत्म हो रहे है।